आरक्षित

उत्तराखंड उच्च न्यायालय में

2017 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 77 में

अखिल कुमार अग्रवाल

……अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य

…… प्रतिवादी.

2017 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 83 के साथ

पंडित विमल कुमार शर्मा

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य. …… प्रतिवादी

2017 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 157 के साथ

जावेद

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य. ……. प्रतिवादी

उपस्थितिः श्री विष्णु चन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता, श्री विपुल गुप्ता, श्री आर एस समल और श्री ललित शर्मा, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री सुभाष त्यागी भारद्वाज, उप महाधिवक्ता, सुश्री ममता जोशी, राज्य के लिए संक्षिप्त होल्डर के साथ।

श्री आर. पी. नौटियाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री हर्षपाल सेखों, मुखबिर के अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त।

निर्णय आरक्षित करने की तिथि: 21.09.2021

सुपुर्द कियाः02. 09. 2019

कोरम: माननीय सुधांशु धूलिया, न्यायाधीश,

माननीय आलोक कुमार वर्मा, ।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा,

ये आपराधिक अपील 22.03.2017 को विद्वान तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा सत्र विचारण संख्या 2011 के 147, राज्य बनाम अखिल कुमार अग्रवाल अग्रेतर दो अन्य द्वारा पारित दोषसिद्धि अग्रेतर सजा के फैसले के विरुद्ध निर्देशित हैं, जिसमें अपीलकर्ता/अभियुक्त अखिल कुमार अग्रवाल को भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 120 बी के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास, भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 364 ए के साथ 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 201 के से दंडनीय अपराध के लिए तीन साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास अग्रेतर भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 120 बी के साथ पढ़े जाने पर 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास अग्रेतर छह महीने के लिए व्यतिक्रम, अपीलकर्ता/विमल कुमार जावेद कुमार शर्मा को भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 364 ए के अन्तर्गत अतिरिक्त आजीवन कारावास

2. अभियोजन का मामला यह है कि 24.11.2010 को सायं 21.30 बजे मुखबिर राकेश गुप्ता, पीडब्लू-1 ने काशीपुर के पुलिस थाने में अपनी तहरीर, एक्सटेंशन का. 1 के माध्यम द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, एक्सटेंशन का. 4 दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उसका पुत्र सचिन गुप्ता बुधवार अर्थात् 24.11.2010 की शाम लगभग 04.00 बजे से लापता था। उसी दिन शाम 6 बजे , जब निवेदक रामनगर में था , उसे उसके बेटे सचिन गुप्ता के फोन से फिरौती के लिए कॉल आया । फोन करने वाले ने उसे सूचित किया कि उसका बेटा सचिन गुप्ता उसकी हिरासत में है और उसने सूचना देने वाले से कहा कि वह उसकी अगली कॉल का इंतजार करे।यह कॉल सूचना देने वाले को अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त हुई।अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल, सचिन गुप्ता के एक करीबी दोस्त था और इसलिए, उन्हें निवेदक द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया.24 नवम्बर, 2010 को, अपीलकर्ता-अखिल कुमार अग्रवाल ने सचिन गुप्ता को उनके (अखिल कुमार अग्रवाल) एक अन्य मोबाइल फोन नं. 9458222568 से अपने मोबाइल फोन पर फोन किया और उन्हें सरकारी अस्पताल, काशीपुर आने के लिए कहा।कथित दिन, अपीलकर्ता-विमल शर्मा और अपीलकर्ता-जावेद को भी अपीलकर्ता-अखिल कुमार अग्रवाल द्वारा अपने मोबाइल नंबर से सरकारी अस्पताल, काशीपुर, 3 में आने के लिए बुलाया गया.मृतक सचिन गुप्ता अपनी मोटरसाइकिल पर काशीपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचा।उसी दिन, लगभग 03.00 बजे अपराह्न में, अपीलकर्ता-विमल शर्मा और अपीलकर्ता जावेद, सचिन गुप्ता के साथ अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा की एक तवेरा कार में रामनगर गए, जिसे सरकारी अस्पताल, काशीपुर से फूल हसन, डीडब्लू 2 द्वारा चलाया गया था और होटल ताज, कॉर्बेट रामनगर में ठहरे थे.मृतक सचिन गुप्ता को अंतिम बार अपीलकर्ता विमल शर्मा और अपीलकर्ता जावेद के साथ अभियोजन पक्ष के गवाह दीपक अरोड़ा-पीडब्लू-४ द्वारा २४. ११. २०१० को देखा गया था.निवेदक ने

अपीलकर्ता-अभियुक्त अखिल कुमार अग्रवाल से उनके बेटे (सचिन गुप्ता) के बारे में पूछा जिस पर अखिल कुमार अग्रवाल ने जवाब दिया कि अगर सचिन का अपहरण किया गया है तो फिरौती की राशि का भुगतान करना और सचिन को बचाना बुद्धिमानी होगी।जब निवेदक और अपीलकर्ता-अखिल कुमार अग्रवाल २४. ११. २०१० की रात में निवेदक के बेटे की तलाश कर रहे थे, तब अपीलकर्ता-अखिल कुमार अग्रवाल ने निवेदक को एक मोटरसाइकिल दिखाई, जो मृतक की थी, और जो सरकारी अस्पताल, काशीपुर के साइकिल स्टैंड पर खड़ी थी.26 नवम्बर, 2010 को निवेदक ने काशीपुर पुलिस थाने में एक और तहरीर प्रस्तुत की कि उसका पुत्र सचिन गुप्ता 24 नवम्बर, 2010 से लापता है।उन्होंने पहले ही एक रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और आज अर्थात 26.11.2010 को उन्हें एक सूचना मिली कि उनके लापता बेटे की हत्या कर दी गई है और उनके बेटे के शव का मुरादाबाद अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है।इसके बाद वह अपने बेटे के शव को काशीपुर ले आए।निवेदक ने एक अन्य तहरीर में अग्रेतर कहा कि उसके मृत बेटे का अपहरण और हत्या अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल द्वारा की गई प्रतीत होती है, जो उसके मृत बेटे और उसके मृत बेटे के करीबी दोस्त हैं, अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के साथ उसके 4 अपहरण से पहले अपने मोबाइल फोन पर संपर्क में थे और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी.दिनांक 26.11.2010 को एक अभियोजन गवाह अर्थात सफदर अली-पीडब्लू-9 ने मुरादाबाद जिले के मुरापंडे पुलिस थाने को एक तहरीरएक्स. का. 9 प्रस्तुत किया कि सड़क के बगल में खाई में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है।उस अवधि के दौरान, मृतक के मोबाइल फोन पर छह बार, संदिग्ध और नकली मोबाइल नंबर 9458222568 से कॉल किए गए थे.मृतक के मोबाइल से फिरौती के लिए फोन करने के समय, मृतक के मोबाइल फोन का स्थान रामनगर में पाया गया।जांच के दौरान, यह पाया गया कि २४. ११. २०१० को, अपीलकर्ता-अखिल कुमार अग्रवाल रामनगर में था.अपीलकर्ता-अखिल कुमार अग्रवाल ने जांच में स्वीकार किया कि संदिग्ध और नकली मोबाइल फोन नं.9458222568 उसका था और उसने अपराध स्वीकार कर लिया।मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के जिला अस्पताल में 26 नवम्बर, 2010 को डॉ. अशोक कुमार-पीडब्ल्यू-3 द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट-एक्स. का. 6 के अनुसार, गला घोंटने के कारण दम घुटना मौत का कारण था।04. 2. 2010 को अपीलकर्ता-विमल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन अपीलकर्ता-विमल शर्मा की पहचान पर पुलिस द्वारा होटल ताज कॉर्बेट, रामनगर के रजिस्टर को अभिरक्षा में ले लिया गया।5 दिसंबर, 2010 को, अपीलकर्ता-विमल शर्मा की पहचान पर एक रस्सी बरामद की गई, जिसका उपयोग अपराध में किया गया था।अपीलकर्ता-जावेद अन्य अपराध में मुरादाबाद जेल में था।मृतक सचिन गुप्ता का बटुआ और कुछ सामान गायब था।27 जनवरी, 2011 को पुलिस ने अपीलकर्ता-जावेद की पहचान पर एक

तवेरा कार, बटुआ और मृतक का लापता सामान बरामद किया।जांच अधिकारी ने कॉल डिटेल की रिपोर्ट एकत्र की और जांच पूरी होने के पश्चात आरोप पत्र दायर किया गया।5

3.तहरीर, एक्सटेंशन का. 1, एक प्राथमिकी एक्सटेंशन का. 4 के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भा.दं.सं. की खंड 364 ए के से केस क्राइम नंबर 577/2010 के रूप में दर्ज किया गया था।अन्वेषण अधिकारी ने निवेदक के घर का स्थल योजना, एक्सटेंशन का. 23, हत्या के हथियार की बरामदगी के स्थान का स्थल योजना, एक्सटेंशन का. 27, मृतक के शव की बरामदगी के स्थान का स्थल योजना, एक्सटेंशन का. 28, तवेरा कार की बरामदगी के स्थान का स्थल योजना, एक्सटेंशन का. 34 तैयार किया।जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए।मृतक के शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल मुरादाबाद में किया गया।जांच पूरी होने पश्चात जांच अधिकारी ने तीन अभियुक्तों अखिल कुमार अग्रवाल, पंडित विमल कुमार शर्मा और जावेद के विरुद्ध भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 302,201,120 बी, 34,414 और 364 ए के अन्तर्गत आरोप पत्र, एक्सटेंशन का. 33 प्रस्तुत किया।

4.यह मामला विद्वत ए. सी. जे. एम., उधम सिंह नगर द्वारा सेशन न्यायाधीश की अदालत को सौंपा था। भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 364 ए, खंड 302 के साथ पठित खंड 34,201 के अन्तर्गत आरोपी अखिल कुमार अग्रवाल के विरुद्ध 14 जुलाई, 2011 को आरोप तय किए गए थे और आरोपी पंडित विमल कुमार शर्मा और जावेद के विरुद्ध 14 जुलाई, 2011 को भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 364 ए, खंड 302 और खंड 34,201 के साथ पठित खंड 120 बी और खंड 414 के से आरोप तय किए गए थे।आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

5. निचली अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, साक्ष्यों की सराहना की और अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन ने आरोपी अखिल कुमार अग्रवाल के विरुद्ध भारतीय विचारण न्यायालय की खंड 120 बी के साथ पठित खंड 364 ए और भारतीय विचारण न्यायालय की खंड 120 बी के साथ पठित खंड 201 और अभियुक्त पंडित विमल कुमार शर्मा और अभियुक्त जावेद के विरुद्ध भारतीय विचारण न्यायालय की खंड 364 ए और भारतीय विचारण न्यायालय की खंड 201 के साथ पठित खंड 120 बी के अन्तर्गत अपने मामले को सफलतापूर्वक साबित

6.विद्वानअपीलार्थियों/अभियुक्त व्यक्तियों के लिए पेश होने वाले विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि यह हत्या का मामला है.यद्यपि यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, वे साबित नहीं हुई हैं और इसलिए अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जा सकता है. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने शरद बर्धी चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116, एच. डी. सिकंद बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2017) 2 एससीसी 116, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,

(1984) 4 एससीसी 116, मामले के निर्णयों पर भरोसा किया।वसीफ हैदर, (2019) 2 एससीसी 303, हट्टी सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2007) 5 स्केल 706, सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2012) 6 एससीसी 403, कंसा बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य, (1987) 3 एससीसी 480, राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) बनाम नवजोत संधू, (2005) 11 एससीसी 600, राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) बनाम नितिन गुणवंत शाह, (2016) 1 एससीसी 472, अनवर पी. वी. बनाम तमिलनाडु राज्य, (2012) 6 एससीसी 403, कंसा बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य, (1987) 3 एससीसी 480, राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) बनाम नवजोत संधू, (2005) 11 एससीसी 600, राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) बनाम नितिन गुणवंत शाह, (2016) 1 एससीसी 472, अनवर पी.पी. के. बशीर और अन्य, (2014) 10 एस. सी. सी. 473, उदय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2015) 16 एस. सी. सी. 17, योगेश बनाम राज्य, (2018) 3 यू. सी. 2101, राज्य बनाम जयदीप और अन्य, मनु/डी. ई./4846/2018, हरपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2017) 1 एस. सी. सी. 734, नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2015) 1 एस. सी. 496, भारत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2003) 3 एस. सी. सी. 106, मोहम्मद.फैजान अहमद उर्फ कालू बनाम बिहार राज्य, (2013) 2 एससीसी 131,2008 की दाण्डिक अपीलीय संख्या 587 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय, राकेश बनाम राज्य, 28.05.2010 को विनिश्चित किया गया।7

7.इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया और प्रस्तुत किया कि अभियोजन ने अपने मामले को सभी उचित संदेह के बाद साबित कर दिया है.

8.हमने श्री विष्णु चन्द्र गुप्ता, श्री विपुल गुप्ता, श्री आर. एस. समल और श्री ललित शर्मा को अपीलार्थियों/अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से पेश होते हुए, श्री सुभाष त्यागी भारद्वाज, उप महाधिवक्ता, सुश्री ममता जोशी के साथ, राज्य के लिए संक्षिप्त होल्डर और श्री आर. पी. नौटियाल, श्री हर्षपाल सेखों, निवेदक की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना।हमारे द्वारा अभिलेख को देखा और उसका अवलोकन किया गया ।

9. यह मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है।किसी ने भी मृतक सचिन गुप्ता पर अपीलार्थियों/अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हमला नहीं देखा था.

10. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलों में, अभियोजन द्वारा भरोसा की गई सभी परिस्थितियों को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और सभी साबित परिस्थितियों को एक पूरी श्रृंखला प्रदान करनी चाहिए।उनकी प्रस्तुतियों के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने शरद बर्धी चंद सारदा (सुप्रा), एच डी

सिकंद (सुप्रा) और हट्टी सिंह (सुप्रा) में निर्णय पर भरोसा किया.एच. डी. सिकंद (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शरद बर्डी चंद सारदा (सुप्रा) के निर्णय को निर्दिष्ट किया।इन मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि जब कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो, तो ऐसे साक्ष्य को इन परीक्षणों को संतुष्ट करना चाहिएःजिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।इस प्रकार स्थापित तथ्यों को मात्र अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ समाविष्ट किया जाना चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्यात्मक नहीं किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को छोड़ देना चाहिए।यह दर्शाने के लिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़े और यह दर्शित किया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा, साक्ष्य की एक श्रृंखला होनी चाहिए।

11. अपीलकर्ता-अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि मुख्य रूप से इन परिस्थितियों पर आधारित है-

(i) अपीलकर्ता-अखिल अग्रवाल ने एक नकली आईडी मोबाइल नंबर 9458222568 प्राप्त किया जिसका उसके द्वारा 05.10.2010 से 24.11.2010 तक उपयोग किया जा रहा था।

(ii) 24.11.2010 को मुखबिर राकेश गुप्ता को मृतक सचिन गुप्ता के मोबाइल नंबर 8923049537 से लगभग 06.03 बजे अपने मोबाइल नंबर 9412091051 पर एक कॉल प्राप्त हुई थी।

(iii) 24.11.2010 को करीब 3 बजे मृतक सचिन गुप्ता अपीलकर्त्ता विमल शर्मा और अपीलकर्त्ता जावेद के साथ गवाह दीपक अरोरा -पी. डब्ल्यू -4. 9 के द्वारा काशीपुर सरकारी अस्पताल के समीप देखा गया ।

(iv)गवाह दीपक अरोरा -पी. डब्ल्यू -4. 9 ने 24.11.2010 को शाम को करीब 6.00 बजे अपीलकर्त्ता विमल शर्मा को अपीलकर्त्ता अखिल कुमार अगरवाल के साथ मानपुर तिराहा , काशीपुर के पास देखा और उस समय अपीलकर्त्ता विमल शर्मा अपने फोन से किसी से बात कर रहा था ।

(v) अपीलकर्ता अखिल अग्रवाल के मोबाइल नंबर 9837667689 की कॉल डिटेल रिपोर्ट के अनुसार, इसका स्थान मानपुर तिराहा, काशीपुर के पास भी पाया गया था।

(vi) 24.11.2010 को लगभग शाम 06.00 बजे, मोबाइल फोन अभिलेख से, अभियुक्त पंडित विमल कुमार शर्मा की उपस्थिति भी मानपुर तिराहा, काशीपुर में स्थित थी।

(vii) मृतक सचिन गुप्ता के मोबाइल का स्थान 24 नवम्बर, 2010 को लगभग 6 बजे काशीपुर में पाया गया। (viii) अपीलकर्त्ता विमल शर्मा , मृतक सचिन गुप्ता और अपीलकर्त्ता जावेद 24 नवम्बर, 2010 को

होटल ताज , कॉर्बेट , रामनगर में रुके । अपीलकर्ता विमल शर्मा और अपीलकर्ता जावेद के प्रकटीकरण बयान के अनुसार मृतक की हत्या में उपयोग की गई सामग्री और मृतक का बटुआ बरामद किया गया।

(x) 04.12.2010 और 05.12.2010 को अपीलकर्ता-विमल शर्मा, होटल रजिस्टर, एक्सटेंशन का. 18 की पहचान पर पुलिस द्वारा होटल ताज, कॉर्बेट, रामनगर से अभिरक्षा में लिया गया और एक रस्सी बरामद की गई, जिसके द्वारा मृतक का गला घोंटा गया था।

(xi) 27.01.2011 को, जबकि अपीलकर्ता जावेद पुलिस हिरासत में था, उसकी पहचान पर, तवेरा 10 कार नंबर यूएस-06/ए-1870, बटुआ और मृतक का अन्य सामान बरामद किया गया।

(xii) मृतक सचिन गुप्ता के बटुए की पहचान उसके पिता ने न्यायालय के समक्ष की थी।

(xiii) 22.11.2010 से 25.11.2010 तक, अपीलकर्ता-अखिल अग्रवाल और अपीलकर्ता जावेद अपने मोबाइल के माध्यम द्वारा एक दूसरे के निकट संपर्क में थे और कॉल डिटेल रिपोर्ट के अनुसार एक दूसरे से बात कर रहे थे।

(xiv) मोबाइल नंबर 9760413695-अपीलकर्ता-विमल शर्मा और मोबाइल नंबर 9897136621-अपीलकर्ता-जावेद एक-दूसरे के लगातार संपर्क में पाए गए और एक-दूसरे से बात की।

(xv) मृतक और अपीलार्थियों की मोबाइल आईडी अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा साबित की गई और अपीलार्थियों द्वारा उक्त मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हुए पाया गया।

12. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए उन्नीस गवाहों की परीक्षा की और बचाव में गवाह कांस्टेबल नवीन चंद्र जोशी-डीडब्ल्यू1 और फूल हसन-डीडब्ल्यू2 की जांच की गई।

13. तर्कसंगत संदेह के बाद सबूत एक दिशानिर्देश है, न कि एक फेटिश और दोषी व्यक्ति अपराध द्वारा बच सकता है क्योंकि सत्य को मानव प्रक्रियाओं के माध्यम से पेश करने पर कुछ कमजोरी होती है।पूर्वाग्रह या पूर्व निर्धारित निष्कर्ष की किसी भी संभावना को बाहर रखा जाना चाहिए।यह कहा जाता है कि एक तथ्य साबित हो जाता है जब, मामले पर विचार करने के पश्चात न्यायालय या तो इससे अस्तित्व मानता है या इसके अस्तित्व की इतनी संभावना पर विचार करता है कि किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर सेर्य करने के लिए कि यह मौजूद है, एक विवेकशील व्यक्ति को चाहिए।11

14.महेन्द्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 11 एस. सी. सी. 334 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्द्र सिंह और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1978) 4 एस. सी. सी. 161 में पहले के निर्णय को निर्दिष्ट किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है, “साक्ष्य, मौखिक और पारिस्थितिक की विश्वसनीयता समग्रता के

न्यायिक मूल्यांकन पर पर्याप्त रूप से निर्भर करती है, न कि पृथक संवीक्षा पर।जबकि यह आवश्यक है कि सभी आपराधिक मामलों में युक्तियुक्त संदेह के बाद सबूत पेश किया जाना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है कि यह परिपूर्ण हो।"

15. पुलिस निरीक्षक बनाम सरवनन और एक अन्य (2008) 17 एस. सी. सी. 587 वाले मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह कहा गया है कि किसी साक्षी के साक्ष्य की सराहना करते हुए, अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित किए बिना तुच्छ मामलों पर मामूली विसंगतियां, न्यायालय को अपने संपूर्ण साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए।इसके अग्रेतर गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य स्वरूप पर, विचारण न्यायालय साक्ष्य के मूल्यांकन पर उसकी विश्वसनीयता के बारे में मत बनाता है, सामान्य परिस्थितियों में अपील न्यायालय को न्यायोचित कारणों के बिना एक बार फिर से इसका पुनर्विलोकन करने के लिए उचित नहीं ठहमता जा सकता है।यह स्थिति की समग्रता है, जिस पर ध्यान देना होगा।कुछ मामूली ब्यौरे में अंतर, जो अन्यथा अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित नहीं करता है, भले ही वह उपस्थित हो, यह स्वयं न्यायालय को मामूली विसंगतियों और विसंगतियों पर साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा।

16. उगर अहीर बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 277 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यूनो में फालसस, ओम्निबस में फालसस न तो कानून का ठोस नियम है और न ही प्रैक्टिस का नियम है।शायद ही कोई ऐसा गवाह मिलता है जिसके साक्ष्य में झूठ का एक दाना या किसी भी तरह की अतिशयोक्ति, कढ़ाई या सजावट नहीं है।अतः न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करे और सुखद रूपक के रूप में अनाज को भूसी से अलग करे।लेकिन, यह स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के मामले के आधार या साक्ष्य के तात्विक हिस्सों पर अविश्वास नहीं कर सकता है और बाकी में से अपनी कहानी का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता है।

17. कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य, (2002) 6 एस. सी. सी. 81 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, 'न्यायालय को साक्ष्य की सराहना करते हुए जीवन की इन वास्तविकताओं को नहीं भूलना चाहिए और हाथीदांत के टावर में बैठकर अवास्तविक दृष्टिकोण नहीं अपना सकता।मैंने पाया है कि हाल के दिनों में किसी आरोपी को आसानी से बरी करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।छोटे निर्णय द्वारा मामले में उठाए गए छोटे बिंदुओं के आधार पर दोषमुक्ति का आदेश पारित करना बहुत आसान है ताकि निपटान का मानदंड प्राप्त किया जा सके।प्रत्येक मामले में कुछ विसंगतियां अवश्य होनी चाहिए जो न्यायालय के साथ तब तक भारित नहीं होनी चाहिए जब तक

कि यह अभियोजन मामले को वस्तुतः प्रभावित नहीं करता है।यदि कंकड़ के क्षेत्र में विसंगतियां इंगित की जाती हैं, तो न्यायालय को उस पर चलना चाहिए, लेकिन यदि वे पत्थर हैं, तो न्यायालय को उस पर कूदने का प्रयास नहीं करना चाहिए।इन दिनों जब अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, मानवता पीड़ित है और समाज इससे इतना प्रभावित हो रहा है, अदालतों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं।अब यह कहावत कि "सौ दोषी व्यक्तियों को बरी कर दिया जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाए" व्यवहार में दुनिया को बदल रही है और अदालतों को यह प्रतिग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि "समाज गलत दोषों से पीड़ित है और वह गलत दोषमुक्ति से समान रूप से पीड़ित है"।मैंने पाया है कि हाल के दिनों में इस न्यायालय ने समय-समय पर इन तथ्यों पर ईमानदारी से ध्यान दिया है।"

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, अब हम अभिलेख पर साक्ष्यों के प्रकाश में दोनों पक्षों के 13 विद्वान अधिवक्ताों की प्रस्तुतियों का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

19.राकेश गुप्ता-पीडब्लू-1 इस मामले में निवेदक है जो मृत सचिन गुप्ता का पिता है।इस साक्षी ने अपने तहरीर, एक्स्ट्रा का. 1 और एक्स्ट्रा. का. 2, एक्स्ट्रा. का. 3 के सचिन गुप्ता के मृत शरीर को साबित किया है और सामग्री 1 से 8 तक प्रदर्शित की है।इस गवाह ने शपथ पर कहा कि अपीलकर्ता-आरोपी अखिल अग्रवाल मृतक सचिन गुप्ता का दोस्त था।यह तथ्य अपीलार्थी-अभियुक्त अखिल अग्रवाल द्वारा अपने अपील के मैदान में स्वीकार किया गया है.

20.अभियोजन पक्ष के गवाह कांस्टेबल नवीन चंद जोशी-पीडब्ल्यू-2 एफआईआर, एक्सटेंशन का अभिदाता है। उन्होंने जी. डी., एक्सटेंशन का. 5.21 भी साबित किया।

21.डॉ. अशोक कुमार-पीडब्ल्यू-3 ने मृतक सचिन गुप्ता के शव का पोस्टमार्टम किया है।इस गवाह ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, एक्स्ट्रा. का. 6. को साबित कर दिया है.

22 . सभी अपीलार्थियों और मृतक सचिन गुप्ता को अभियोजन पक्ष के गवाह दीपक अरोड़ा, पीडब्लू-४, ने २४. ११. २०१० को देखा था.

23. अभियोजन गवाह मकबूल हुसैन, पीडब्लू-5, मृतक सचिन गुप्ता के मृत शरीर के पंचनामा का गवाह है और उसने जांच रिपोर्ट, एक्जिट का. 7, खून से सना हुआ मिट्टी का टुकड़ा, एक्जिट का. 8 और सामग्री प्रदर्शनी 10 से 16.

24. को साबित किया।अभियोजन पक्ष के गवाह रईस अहमद, पीडब्लू-6, होटल ताज कॉर्बेट, रामनगर का मालिक है।इस गवाह ने साबित किया है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त विमल कुमार शर्मा और अन्य मृतक सचिन गुप्ता सहित सभी तीन व्यक्तियों में 24.11.2010 को उसके 14 होटल में रहे।इस गवाह ने मृतक सचिन गुप्ता, एक्सटेंशन 17 और होटल रजिस्टर, एक्सटेंशन 18.25 की फोटो को साबित कर दिया है।

25.अभियोजन गवाह कांस्टेबल दीपक कथैत, पीडब्लू7 ने मृतक का बटुआ और घटना में उपयोग किए गए वाहन तवेरा और 27.01.2011-एक्जिट. का. 30.

26. को रिकवरी फ़र्ड को साबित कर दिया है।अभियोजन पक्ष के गवाह जमील अहमद, पीडब्लू-8 ने 27 जनवरी, 2011 को अपीलकर्ता-अभियुक्त जावेद और तवेरा कार से बरामद बटुए की पहचान की है।इस गवाह ने कहा है कि उसके हस्ताक्षर ज्ञापन, एक्सटेंशन 30 पर हैं.

27 .अभियोजन पक्ष के गवाह सफदर अली, पीडब्लू-9 गवाह हैं जिन्होंने 26.11.2010 को पुलिस स्टेशन को अज्ञात शव के बारे में जानकारी दी थी।इस गवाह ने पंचनामा, एक्सटेंशन का. 7 और खून से सना हुआ मिट्टी का ढेर, एक्सटेंशन का. 8 और अज्ञात मृत शरीर सूचना रिपोर्ट, एक्सटेंशन का. 9. को साबित किया है .

28. अभियोजन पक्ष के गवाह ऋषि कपूर, पीडब्लू 10 मुरापंडे पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी थे।इस गवाह ने मृत सचिन गुप्ता, एक्सटेंशन का. 7 के मृत शरीर का पंचनामा और खून से सने मिट्टी का ज्ञापन, एक्सटेंशन का. 8 साबित कर दिया है।उन्होंने जी. डी. में पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया और प्रविष्टि और मृत सचिन गुप्ता की फोटो सहित सामग्री प्रदर्शनी 11 से प्रदर्शनी 18, प्रदर्शनी 22 से प्रदर्शनी 26. को भी साबित किया है .

29 .सब-इंस्पेक्टर नरेश पाल सिंह, पीडब्ल्यू-11, उस रस्सी की बरामदगी का गवाह है जिसका उपयोग मृतक की हत्या में किया गया था.इस गवाह ने अपीलकर्ता-विमल शर्मा की पहचान पर कथित रस्सी को बरामद किया.गवाह पीडब्लू-१५ ११ ने कथित रस्सी और उसके पैकिंग कपड़े, एक्सटेंशन १६. ३० तक साबित कर दिए हैं.

30.निरीक्षक आर. एस. असवाल-पीडब्ल्यू-12 ने रामनगर के होटल ताज कॉर्बेट के होटल रजिस्टर एक्स. का. 20 की बरामदगी की पुष्टि की।अभियोजन पक्ष के अनुसार, होटल रजिस्टर की वसूली अपीलकर्ता-विमल शर्मा, जीडी, एक्सटेंशन का. 21, एक्सटेंशन का. 22 और होटल रजिस्टर, एक्सटेंशन का. 18 की पहचान के आधार पर की गई थी।

31.गवाह रवींद्र कुमार, पीडब्लू-13, जांच अधिकारी है।उन्होंने नरेश चंद्रा, पीडब्ल्यू-14 से कॉल डिटेल रिपोर्ट यानी 5 के/1 से 5 के/11 और 5 के/73 से 5 के/128 का संग्रह किया था।उन्होंने जांच के दौरान अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया।इंस्पेक्टर नरेश चंद्रा, पीडब्लू-14, तत्कालीन एसओजी ने एक्सटीकेए-25 पत्र को साबित कर दिया था, जो उसे जांच अधिकारी, रवींद्र कुमार, पीडब्लू-13 से प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा उक्त कॉल विवरण रिपोर्टों की आवश्यकता थी।

32.इंस्पेक्टर नरेश चंद्रा, पीडब्लू १४, ने कहा कि उन्होंने जांच अधिकारी, रविन्द्र कुमार, पीडब्लू १३. ३३ को कॉल डिटेल रिपोर्ट अर्थात् प्रदर्शनी, ५ के/१ से ५ के/११ और ५ के/७३ से ५ के/१२८ सौंप दी.

33.गवाह सर्वेश कुमार, पीडब्लू15, जूनियर टेलीकॉम अधिकारी, बीएसएनएल है। इस गवाह ने लैंडलाइन नंबर 05947-278170 को साबित किया था जो अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल का है और उसे उसके आवासीय घर पर स्थापित किया गया था।

34.साक्षी हुसैन एम. जादी, पीडब्ल्यू16, आइडिया सेल्युलर कंपनी में एक नोडल अधिकारी हैं।इस गवाह ने अपीलकर्ता अखिल अग्रवाल के मोबाइल नंबर 9837667689 और 16 अपीलकर्ता अखिल अग्रवाल के भाई तुषार अग्रवाल के मोबाइल नंबर 9837373774 को प्रमाणित और साबित किया था.इस गवाह ने इन मोबाइल फोनों अर्थात् एक्सटीकेए. 37 और एक्सटीकेए. 38 की आईडी और कॉल डिटेल रिपोर्ट को साबित कर दिया था, जो एसओजी 35 को सौंपी गई थीं।

35.गवाह राधे श्याम शुक्ला, पीडब्लू 17, एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी हैं।इस गवाह ने अपीलकर्ता जावेद की आईडी और मोबाइल नंबर 9897136621 और अपीलकर्ता विमल शर्मा की मोबाइल नंबर 9760413695 की आईडी को साबित किया था, जो एक्सटेंशन का. 39 और एक्सटेंशन का. 40 हैं।इस गवाह ने एसओजी 36 को सौंपी गई कॉल डिटेल रिपोर्ट को भी साबित कर दिया है।

36.गवाह अमित कुमार गंगवार, पीडब्लू 18, यूनिनॉर कंपनी के नोडल अधिकारी हैं।इस गवाह ने मृतक सचिन गुप्ता के मोबाइल नंबर 8923049537, एक्सटेंशन का. 41 की आईडी साबित कर दी है।इस गवाह ने यह साबित कर दिया है कि उसने कॉल डिटेल रिपोर्ट एस. ओ. जी. 37 को सौंप दी।

37.गवाह विष्णु गोपाल उपाध्याय, पीडब्लू 19 सेवानिवृत्त सब-इंस्पेक्टर हैं, जो तब मुरादाबाद जिले के मुरापंडे पुलिस स्टेशन में तैनात थे।इस गवाह ने 26.11.2010 को की गई जांच की कार्यवाही और अन्य बरामदगी की सामग्री एक्सटेंशन का. 37 को साबित कर दिया है, जिसे इस गवाह द्वारा कोतवाली काशीपुर भेजा गया था।उसने पुलिस स्टेशन काशीपुर को एक पत्र भेजा कि बरामद मृत शरीर गुमशुदा सचिन गुप्ता का है, जिसका मामला 2010 की अपराध संख्या 577 के रूप में पुलिस स्टेशन काशीपुर में दर्ज किया गया था।

38.दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों की परीक्षा पश्चात अपीलार्थी-अभियुक्त व्यक्तियों ने अपनी प्रतिरक्षा में दो गवाहों खंड पूछताछ की।

39.गवाह नवीन जोशी, डीडब्ल्यू1 एक कांस्टेबल है।इस गवाह ने 24.11.2010 से 17 27.11.2010 तक पुलिस स्टेशन काशीपुर, एक्सटेंशन खा. 1 से एक्सटेंशन खा. 4.40 की जी. डी. की प्रविष्टियों को साबित कर दिया है।

40.गवाह फूल हसन, डीडब्ल्यू2 ने अपनी परीक्षा-इन-चीफ में कहा है कि वह अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है और वह अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा के ड्राइवर के रूप में काम नहीं कर रहा था.

41.निवेदक राकेश गुप्ता, पीडब्ल्यू1 ने कहा है कि उनकी एक दुकान है।24 नवम्बर, 2010, बुधवार को बाजार बंद रहा।उसकी दुकान साफ-सफाई के लिए खुली थी।उनके पुत्र सचिन गुप्ता निवेदक के दोपहर के भोजन के साथ दोपहर लगभग 2 बजे अपने आवास से उनकी दुकान पर आए।उसके बाद बेटा चला गया।निवेदक राकेश गुप्ता, पीडब्लू-1 और गवाह दीपक अरोड़ा, पीडब्लू-4 उधम सिंह नगर के मोहल्ला रहमखानी, काशीपुर के निवासी हैं।गवाह दीपक अरोड़ा, पीडब्लू 4 एक पीसीओ चला रहा है जो रोड वेज बस स्टॉप, काशीपुर के पास स्थित है।इस गवाह ने शपथ पर कहा है कि वह अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल को जानते हैं, जो इस गवाह के साक्ष्य के समय अदालत में उपस्थित थे, और कहा कि लगभग 24.11.2010 को अपराह्न 3.00 बजे, उन्होंने सचिन गुप्ता को देखा, जो अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा और अपीलकर्ता जावेद से बात कर रहे थे, दोनों ठाकुरद्वारा के निवासी हैं और जो सरकारी अस्पताल, काशीपुर के सामने इस गवाह के साक्ष्य के समय अदालत में उपस्थित थे।इस गवाह ने कहा है कि उसने अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल की दुकान में कई बार इन दो अपीलार्थियों को देखा था.गवाह दीपक अरोड़ा, पीडब्लू ४, ने अग्रेतर कहा कि अपीलकर्ता जावेद और अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा बढ़ई का काम कर रहे हैं और दोनों इस गवाह के पीसीओ में आते थे.अपीलकर्ता-अखिल कुमार अग्रवाल ने इस गवाह के साक्ष्य का खंडन नहीं किया कि अपीलकर्ता की एक दुकान है और इस गवाह ने कई बार अपीलकर्ता विमल कुमार 18 शर्मा और अपीलकर्ता जावेद को अपनी (अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल) दुकान में देखा था और अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा और अपीलकर्ता जावेद की ओर से इस गवाह के साक्ष्य के विरुद्ध कोई सुझाव नहीं है कि ये दोनों अपीलकर्ता अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल की दुकान पर जाते थे.इसलिए गवाह दीपक अरोड़ा, पीडब्ल्यू4 के इन सबूतों का खंडन नहीं किया गया है।

42.गवाह पीडब्लू 4 दीपक अरोड़ा ने कहा कि उसने सचिन गुप्ता से पूछा कि वह वहां क्यों खड़ा था।सचिन गुप्ता ने उसे बताया कि वह अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा और अपीलकर्ता जावेद के साथ रामनगर जा रहा था और फिर सचिन गुप्ता अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा और अपीलकर्ता जावेद के साथ तवेरा कार में रामनगर गए.ये बयान इस गवाह द्वारा जांच अधिकारी, रविंद्र कुमार, पीडब्लू 13 को भी दिए गए थे.इस गवाह ने शपथ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा को लगभग 06 बजे मानपुर तिराहा, काशीपुर के पास अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के साथ देखा थाःउस समय अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था।

43.अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि गवाह दीपक अरोड़ा, पीडब्लू 4, निवेदक का पड़ोसी है, और परिणामस्वरूप, एक हितबद्ध गवाह होने के नाते, उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है.

44. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि साक्षी दीपक अरोड़ा, पी डब्लू 4, हितबद्ध साक्षी नहीं है।उपर्युक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह दीपक अरोड़ा, पी डब्लू ४. १९ ४५, के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर विचार करे.

45.बेंथम के अनुसार, गवाह न्यायाधीश की आंख और कान हैं।एक गवाह को आमतौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह उन स्रोतों से उत्पन्न नहीं होता है जिनके दागदार होने की संभावना है और आमतौर पर इसका मतलब है, जब तक कि गवाह के पास अपीलकर्ताओं के विरुद्ध उन्हें गलत तरीके से फंसाने की इच्छा न हो।पी डब्लू 4 के दीपक अरोड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी निवेदक के साथ कोई मित्रता नहीं है।अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि यह साक्षी अपीलार्थियों के लिए शत्रुतापूर्ण है और जब साक्षी, जिसे अभियोजन में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है या अपीलार्थियों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं दिखाया गया है, को निस्स्वार्थ साक्षी माना जाना चाहिए.दीपक अरोड़ा-पीडब्ल्यू-4 के साक्ष्य को मात्र इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि वह एक पड़ोसी है। अपीलार्थियों द्वारा ऐसा कुछ भी सामने नहीं लाया गया है, जो किसी भी तरह से इस गवाह के साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा करे.इस गवाह की गवाही को मात्र इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह उस इलाके का निवासी है, जहां निवेदक रहता है, जब तक कि प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य को हिलाया नहीं जाता है या इस गवाह का व्यवहार इस तरह का नहीं है कि यह अपरिहार्य निष्कर्ष है कि उसका साक्ष्य संदिग्ध है.मामूली अंतर और विरोधाभास अपीलार्थियों के पक्ष में संदेह के लाभ को झुकाव नहीं देंगे.इसलिए, हम इस गवाह के पूरे साक्ष्य के अवलोकन से संतुष्ट हैं कि उसका साक्ष्य भरोसेमंद और पूरी तरह से विश्वसनीय है.

46.अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा और अपीलकर्ता जावेद मृतक के साथ सरकारी अस्पताल, काशीपुर के स्थान से तवेरा कार में रामनगर में स्थित होटल ताज कॉर्बेट गए थे।अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा को 04 दिसम्बर, 2010 को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा की पहचान पर होटल ताज कॉर्बेट के आगंतुकों के रजिस्टर को अभिरक्षा में ले लिया।कथित होटल रजिस्टर में, एक्सटी. का. १८, २० प्रविष्टि स्वयं अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा द्वारा की गई थी.

47.गवाह रईस अहमद, पीडब्लू 6, होटल ताज कॉर्बेट का मालिक है।उसने अपनी परीक्षा में कहा है कि ०४. १२. २०१० को कोतवाल काशीपुर और जांच अधिकारी रविन्द्र कुमार अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा के साथ उसके होटल में आए जहां उन्होंने इस होटल के आगंतुक रजिस्टर की जांच की और उसे अपने साथ सीलबंद लिफाफे में ले गए, जिसमें आगंतुकों का विवरण दर्ज किया गया है.होटल विजिटर्स रजिस्टर, एक्सटेंशन का. 20 का ज्ञापन पीडब्ल्यू6 के रईस अहमद द्वारा साबित किया गया है।उन्होंने एक्सटीकेए 20 पर अपने हस्ताक्षर साबित किए।

गवाह रईस अहमद, पी डब्लू ६, ने अपनी परीक्षा-इन-चीफ में कहा कि इस रजिस्टर की क्रम संख्या २४० पर, अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा द्वारा अपने हाथ में प्रविष्टि की गई है और २४. १०. २०१० को शाम ५. ०० बजे इस गवाह से पहले अपने वाहन और अपने मोबाइल फोन की संख्या रिकॉर्ड की गई है.उन्होंने अग्रेतर कहा कि वे तीन व्यक्ति थे और होटल रजिस्टर में, अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा ने अपने मोबाइल नंबर 9760413695 का उल्लेख किया है.गवाह रईस अहमद, पी डब्लू ६, ने मृतक की तस्वीर देखने के पश्चात अपनी परीक्षा-प्रधान में कहा कि मृतक अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा और एक अन्य व्यक्ति के साथ २४. ११. २०१० को उसके होटल में आया था.यद्यपि उन्होंने यह नहीं बताया कि अदालत में मौजूद दो आरोपी कौन हैं।इसलिए, अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर, विद्वान निचली विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को इस गवाह से प्रश्न पूछने की अनुमति दी, जिसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकती है.अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गवाह रईस अहमद, पीडब्लू 6, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है, इसलिए, पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला विफल हो गई है। अपीलकर्ताओं के लिए 21 विद्वान अधिवक्तातों की प्रस्तुतीकरण स्वीकार्य नहीं है.यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मात्र इसलिए कि किसी गवाह को प्रतिकूल घोषित किया जाता है, उसके साक्ष्य को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।यदि किसी विरोधी गवाह के साक्ष्य का कोई भाग सही पाया जाता है तो न्यायालय उसके साक्ष्य के ऐसे भाग पर भरोसा कर सकता है।राजेन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 13 एस. सी. सी. 48 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि मात्र एक साक्षी के कारण, उसके कथन से विचलित होता है, उसके साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है।गोविंदप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (2010) 6 एससीसी 533 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी प्रतिकूल गवाह के बयान पर कम से कम उस सीमा तक भरोसा किया जा सकता है जहां तक उसने अभियोजन के मामले का समर्थन किया था।रईस अहमद, पी डब्लू 6 के साक्ष्य की पुष्टि निरीक्षक आर एस असवाल, पी डब्लू 12 और गवाह रविन्द्र कुमार, पी डब्लू 13, जांच अधिकारी के साक्ष्य द्वारा की गई है।होटल ताज कॉर्बेट, रामनगर के आगंतुक रजिस्टर को गवाह निरीक्षक आर. एस. असवाल, पीडब्लू 12 की उपस्थिति में हिरासत में ले लिया गया।निरीक्षक आर. एस. असवाल, पी डब्लू १२ और गवाह रविन्द्र कुमार, पी डब्लू १३ ने कहा है कि ०४. १२. २०१० को होटल ताज कॉर्बेट, रामनगर के आगंतुक रजिस्टर को हिरासत में ले लिया गया था और उस समय अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा वहां मौजूद था.इन सबूतों के विरुद्ध अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा की ओर से कोई सुझाव नहीं है.इसलिए इन सबूतों का खंडन नहीं किया जा सकता।उपर्युक्त रजिस्टर के अनुसार, तवेरा कार की पंजीकरण संख्या यूए 06 एच-1870 और अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा का मोबाइल फोन नंबर 9760413695 05:यह भी ध्यान देने योग्य है कि गवाह रईस अहमद ने मृतक

सचिन गुप्ता की तस्वीर की पहचान की है।बचाव पक्ष के गवाह फूल हसन, डीडब्ल्यू2 ने कहा है कि वह तवेरा कार का चालक नहीं था, लेकिन इस एकमात्र बयान पर, अभियोजन पक्ष के विश्वसनीय साक्ष्यों को खारिज नहीं किया जा सकता है.जबकि 22 ने कहा कि अपीलकर्ता जावेद की पहचान पर तवेरा कार 27.01.2011 को बरामद की गई थी।अपीलार्थी यह नहीं दिखा सके कि कांस्टेबल नवीन चंद्र जोशी, डीडब्ल्यू१, के साक्ष्य के आलोक में, अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो जाता है.50. अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल का मात्र कनेक्शन मोबाइल फोन है, और उसमें कॉल हैं।अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के विद्वान अधिवक्ता बनाम दिया कि मोबाइल फोन कंपनी के चार अधिकारियों, अर्थात्, गवाह सर्वेश कुमार, पीडब्लू 15, बीएसएनएल के अधिकारी, हुसैन एम. जादी, पीडब्लू 16, आइडिया खंडल्युलर कंपनी के नोडल अधिकारी, राधे श्याम शुक्ला, पीडब्लू 17, एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी और अमित कुमार गंगवार, पीडब्लू 18, यूनिनॉर कंपनी के नोडल अधिकारी, साक्ष्यों में स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि मोबाइल कॉल का विवरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं होता है, इस मामले में योगेश (सुप्रा), दिल्ली राज्य (एनसीटी). नवजोत संधू (सुप्रा), उदय कुमार (सुप्रा), हरपाल सिंह (सुप्रा), दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में।माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनवर पी. वी. बनाम भारत संघ वाले मामले में यह मत व्यक्त किया। पी. के. बशीर और अन्य, (2014) 10 एस. सी. सी. 473, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम नवजोत संधू के निर्णय को निर्दिष्ट किया है, पैरा सं.धारा 59 और 65-ए को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य अधिनियम के से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम खंड कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य धारा 65-बी के से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मात्र 23 में साबित किया जा सकता है।इन प्रावधानों का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में द्वितीयक साक्ष्य को पवित्र करना है, जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है।यह नोट किया जा सकता है कि यह खंड एक सर्वोपरि खंड से प्रारंभ होती है।इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रोनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट कोई भी जानकारी, जो किसी कागज अग्रेतर मुद्रित है, किसी कम्प्यूटर द्वारा ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में भंडारित, अभिलिखित या प्रतिलिपित है, मात्र तभी दस्तावेज समझी जाएगी जब उपधारा (2) से उल्लिखित शर्तें, मूल के अतिरिक्त सबूत या उत्पादन के बिना, पूरी हो जाती हैं।इस तरह के दस्तावेज यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिखंड कंप्यूटर आउटपुट कहा जाता है, की स्वीकार्यता धारा 65-बी (2) के से चार शर्तों की संतुष्टि पर निर्भर करती है।साक्ष्य अधिनियम की खंड 65-बी (2) के से निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित हैं:इस अवधि के दौरान, कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा था और यदि यह कुछ समय के लिए ठीक से काम नहीं कर

रहा था, तो टूटने या टूटने से उसकी सामग्री की अभिलेख सटीकता या सटीकता प्रभावित नहीं हुई थी।15. साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी (4) से तहत, यदि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख खंड संबंधित किसी भी कार्यवाही में एक बयान देने की इच्छा है, तो यह अनुज्ञेय है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:(ग) प्रमाणपत्र को उस अभिलेख के पेश किए जाने से अंतर्वलित खंड के ब्यौरे अवश्य प्रस्तुत करने चाहिए।यह अग्रेतर स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति को मात्र प्रमाण पत्र में यह कहने की आवश्यकता है कि यह उसकी जानकारी और विश्वास का सर्वश्रेष्ठ है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह का प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जैसे कंप्यूटर प्रिंटआउट, कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी), वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क (वीसीडी), पेन ड्राइव आदि के साथ होना चाहिए, जिसके संबंध में साक्ष्य के रूप में एक बयान प्रस्तुत किया जाता है।ये सभी सुरक्षा उपाय स्रोत और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित दो हॉलमार्क हैं, जिनका उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जाना है।ऐसे सुरक्षा उपायों के बिना इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के छेड़छाड़, परिवर्तन, स्थानांतरण, निष्कासन आदि के प्रति अधिक संवेदनशील होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के सबूत के आधार पर पूरा विचारण न्यायाधीश का उपहास कर सकता है।17. मात्र यदि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ख के संदर्भ में सम्यक रूप खंड प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी वास्तविकता के बारे में प्रश्न उठेगा और उस स्थिति में, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की धारा 45-क की मत ली जा सकती है।18. साक्ष्य अधिनियम मौखिक साक्ष्य द्वारा इलैक्ट्रानिक अभिलेख के सबूत की संकल्पना या अनुज्ञा नहीं देता है यदि साक्ष्य अधिनियम की खंड 65-ख से अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, जैसा कि अब भारत में विधि विद्यमान है।धारा 59 और 65-ख के साथ पठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-क का शीर्षक यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख खंड संबंधित साक्ष्य पर विशेष उपबंध साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ख से विहित प्रक्रिया द्वारा शासित होंगे।एक विशेष कानून होने के नाते, धारा 63 और 65 के से सामान्य कानून को झुकना पड़ता है।21. राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) बनाम नवजोत संधू के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ को साक्ष्य के रूप में इलैक्ट्रानिक अभिलेख के पेश किए जाने के मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला।सेलफोन से संबंधित कॉलों के कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्डों के प्रिंटआउट पर विचार करते समय, यह पैरा 150 पर निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:(एस. सी. सी. पृष्ठ 714) '150. धारा 63 के अनुसार,' द्वितीयक साक्ष्य 'खंड अभिप्रेत है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ' यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल खंड 25 प्रतियां बनाई गई हैं जो अपने आप में प्रतिलिपि की सटीकता और प्रतिलिपियां ऐसी प्रतियों की तुलना में सुनिश्चित करती हैं '।धारा 65 किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाती है यदि मूल इस प्रकार की प्रकृति की है जो आसानी खंड

चल नहीं सकती है।इसमें कोई विवाद नहीं है कि कॉल रिकॉर्ड में निहित जानकारी बड़े सर्वर में संग्रहीत है जिसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है।उच्च न्यायालय ने भी पैरा 276 में यही विचार व्यक्त किया है।अतः यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कम्प्यूटरों/सर्वरों द्वारा लिए गए प्रिंटआउट और द्वारावा प्रदान करने वाली कंपनी के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए प्रिंटआउट को साक्षी के माध्यम द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो प्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षरों की पहचान कर सकता है या अन्यथा अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर तथ्यों का उल्लेख कर सकता है।धारा 65-बी, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता खंड संबंधित एक प्रावधान है, की आवश्यकताओं के अनुपालन के बावजूद, साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों, अर्थात् धारा 63 और 65 के से द्वितीयक साक्ष्य को शामिल करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।यह हो सकता है कि धारा 65-ख की उपधारा (4) में दिए गए ब्यौरे वाला प्रमाणपत्र तत्काल मामले में दाखिल नहीं किया गया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि द्वितीयक साक्ष्य तब भी नहीं दिया जा सकता है जब कानून ऐखंड साक्ष्य को सुसंगत उपबंधों, अर्थात् धारा 63 और 65 में उल्लिखित परिस्थितियों में दिए जाने की अनुमति देता है।यह देखा जा सकता है कि यह एक ऐसा मामला था जहां एक जिम्मेदार अधिकारी ने उत्पादन के समय ही दस्तावेज को विधिवत प्रमाणित कर दिया था।प्रमाणपत्र में हस्ताक्षरों की भी पहचान की गई थी।यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 65-ख, जो इलैक्ट्रानिक अभिलेख की ग्राह्यता खंड संबंधित एक विशेष उपबंध है, की अपेक्षाओं के अनुपालन के बावजूद, इलैक्ट्रानिक अभिलेख की धारा 63 और 65 से द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई वर्जन नहीं है।22. इलैक्ट्रानिक अभिलेख खंड संबंधित साक्ष्य, जैसा कि इसमें पहले उल्लेख किया गया है, एक विशेष उपबंध होने के नाते, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के साथ पठित धारा 63 से द्वितीयक साक्ष्य पर सामान्य विधि उसी के अनुरूप होगी।सामान्य कानून पर विशेष कानून हमेशा हावी रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने इलैक्ट्रानिक अभिलेख की ग्राह्यता से संबंधित धारा 59 और 65-क पर ध्यान नहीं दिया।26 उस सीमा तक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर कानून का बयान, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नवजोत संधू मामले में कहा गया है, सही कानूनी स्थिति को निर्धारित नहीं करता है।इसे पलटने की जरूरत है और हम ऐसा करते हैं।द्वितीयक साक्ष्य के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि खंड 65-बी के से आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है।इस प्रकार, सीडी, वीसीडी, चिप आदि के मामले में, दस्तावेज लेते समय प्राप्त धारा 65-बी के संदर्भ में प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए, जिसके बिना उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख खंड संबंधित द्वितीयक साक्ष्य अस्वीकार्य है।24. स्थिति भिन्न होती यदि अपीलकर्ता ने साक्ष्य में, घोषणा और गानों के लिए उपयोग की जाने

वाली सीडी को उपलब्ध कराकर, प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत किया होता।अगर आपत्तिजनक गीतों या घोषणाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीडी को पुलिस या चुनाव आयोग के माध्यम द्वारा जब्त कर लिया जाता और उद्वारा प्राथमिक सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता तो उच्च न्यायालय यह देखने के लिए अदालत में खेल सकता था कि आरोप सही हैं या नहीं।इस मामले में स्थिति ऐसी नहीं है।भाषणों, गीतों और घोषणाओं को अन्य उपकरणों का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया और उन्हें कंप्यूटर में डालकर सीडी बनाई गई, जिन्हें उचित प्रमाणन के बिना अदालत में पेश किया गया।उन सीडी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की खंड 65-बी की अनिवार्य अपेक्षाएं संतुष्ट नहीं हैं।यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की खंड 59,65-ए और 65-बी के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के द्वितीयक साक्ष्य पर पिछले पैराग्राफ में हमने जो कहा है, उसके बावजूद, यदि इस तरह के एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का साक्ष्य अधिनियम की खंड 62 के बनाम प्राथमिक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वह साक्ष्य अधिनियम की खंड 65-बी में शर्तों के अनुपालन के बिना साक्ष्य में स्वीकार्य है।- 13.4.उच्च न्यायालय ने अग्रेतर पाया कि प्रिंटआउट, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, साक्ष्य अधिनियम की खंड 65-ख के उपबंधों के अनुसार साबित नहीं किया गया है।इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया कि कथित प्रिंटआउट को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा."" "माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (पूर्वोक्त) वाले मामले में यह मत व्यक्त किया हैः\" "" ""कॉल डिटेल्स की स्वीकार्यता का हवाला देते हुए, यह एक अभिलेख की बात है कि हालांकि पीडब्लूएस 24,25,26 और 27 ने सामान्य व्यवसाय में रखे गए और कंपनी सर्वर के एक हार्ड डिस्क में संग्रहीत कंप्यूटर खंड उत्पन्न कॉल डिटेल्स की मुद्रित प्रति के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया है, आरोपी व्यक्तियों खंड बरामद किए गए अन्य लोगों के साथ-साथ इसमें शामिल खंडलफोनों खंड की गई कॉलों को सह-संबंधित करने के लिए, अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 65-बी (4) के से आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा हैजैसा कि जाहिर है कि अभियोजन पक्ष ने कॉल विवरण की मुद्रित प्रति के रूप में द्वितीयक साक्ष्य पर भरोसा किया है, यहां तक कि यह मानते हुए कि धारा 65-बी (2) के आदेश का अनुपालन किया गया था, धारा 65-बी (4) के से एक प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में में, उखंड साक्ष्य में अस्वीकार्य माना जाना चाहिए.इस न्यायालय ने अनवर पी. वी. में यह अभिनिर्धारित किया है कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख खंड संबंधित साक्ष्य एक विशेष उपबंध होने के कारण, अधिनियम की धारा 65 के साथ पठित धारा 63 से द्वितीयक साक्ष्य पर सामान्य विधि को उसके समक्ष प्रस्तुत करना होगा।यह प्रतिपादित किया गया है कि द्वितीयक साक्ष्य के रूप में कोई भी विद्युत अभिलेख साक्ष्य

में तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि खंड 65-बी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 65-ए और 65-बी से संबंधित कानून की व्याख्या को देखते हुए हमारा यह निष्कर्ष अपरिहार्य है।राज्य बनाम जयदीप और अन्य, मनु/डीई/4846/2018 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनवर पी. वी. (सुप्रा) के फैसले को संदर्भित किया, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख खंड संबंधित साक्ष्य, जैसा कि इसमें पहले उल्लेख किया गया है, एक विशेष प्रावधान है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के साथ पठित धारा 63 के से द्वितीयक साक्ष्य पर सामान्य कानून उसी के अनुरूप होगा। विशेष कानून सामान्य कानून से हमेशा ऊपर रहेगा । ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय ने इलैक्ट्रानिक अभिलेख की ग्राह्यता से संबंधित धारा 59 और 65 क पर ध्यान नहीं दिया।सीमा 63 और 65 का इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के रूप में द्वितीयक साक्ष्य के मामले में कोई प्रयोग नहीं है, यह पूर्णतः सीमा 65 क और 65 ख द्वारा शासित है।इसे पलटने की जरूरत है और हम ऐसा करते हैं।द्वितीयक साक्ष्य से रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि खंड 65 बी से तहत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। इस प्रकार, सीडी, वीसीडी, चिप आदि के मामले में, दस्तावेज लेते समय प्राप्त धारा 65 बी के संदर्भ में प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए, जिसके बिना उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख खंड संबंधित द्वितीयक साक्ष्य अस्वीकार्य है।इस मामले में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनू बनाम हरियाणा राज्य, (2017) 8 एससीसी 570 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपराधिक जांच और अभियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।29 खंड 65 बी (4) का निर्वचन करते हुए, इस न्यायालय ने अनवर के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख उसमें यथा उपबंधित प्रमाणन के बिना साक्ष्य में अग्राह्य है।नवजोत संधू का मामला, जो इसके विपरीत था, खारिज कर दिया गया।योगेश बनाम राज्य (पूर्वोक्त) के मामले में, उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की खंड 65-बी के अनुसार विवरण साबित नहीं किया है.यहां मोबाइल हैंडसेट फोन और लैंडलाइन फोन के विवरण का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जो इस मामले में शामिल थे, ताकि अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूतों की बेहतर सराहना की जा सके।इससे विवरण इस प्रसेर हैः सूचना देने वाले राकेश गुप्ता का सिम नंबर 9412091051, जिस पर फिरौती की कॉल प्राप्त हुई थी।मृतक का मोबाइल फोन जिस पर मृतक का सिम नंबर 8923049537 था, जिसका इस अपराध में उपयोग किया गया था।मोबाइल फोन, एक्सटेंशन 27 में अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल का सिम नंबर 9837667689 है, जिसका इस अपराध में उपयोग किया गया था।यह मोबाइल फोन पुलिस द्वारा इस अपीलकर्ता के कब्जे से 27.11.2010 को बरामद किया

गया था।मोबाइल फोन जिस पर सिम नंबर 9458222568 था, उसका उपयोग अपीलार्थी अखिल कुमार अग्रवाल द्वारा किया जा रहा था.वह इस मोबाइल फोन से मृतक सचिन गुप्ता के मोबाइल फोन पर मृतक से बात करता था।(v) मोबाइल फोन, एक्सटेंशन 28, जिस पर अपीलकर्ता-पंडित विमल कुमार शर्मा का सिम नंबर 9760413695 था, जिसका इस अपराध में उपयोग किया गया था।यह मोबाइल फोन पुलिस द्वारा इस अपीलकर्ता के कब्जे से दिनांक 04.12.2010 को बरामद किया गया था।30 (vi) मोबाइल फोन पर सिम नंबर 9897136621 का उपयोग अपीलकर्ता-जावेद द्वारा किया जा रहा था।यह मोबाइल फोन इस अपराध में शामिल था।(vii) अपीलकर्ता-अखिल कुमार अग्रवाल की आईडी पर मोबाइल फोन, जिस पर सिम नंबर 9927715875 था, अखिल कुमार अग्रवाल की पत्नी द्वारा उपयोग किया जा रहा था.इस मोबाइल फोन पर 07.10.2010 को मोबाइल नम्बर 9458222568 से एक कॉल की गई थी।(viii) अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के घर का लैंडलाइन फोन नंबर 05947-278170.इस लैंडलाइन फोन पर मोबाइल नम्बर 9458222568.53 से कॉल की गई।मोबाइल फोन इसके मालिकों द्वारा हर समय ले जाया जाता है, और फोन के सिग्नल को प्रसारित करने वाले स्थानीय मोबाइल बेस स्टेशनों से लगातार जुड़ा रहता है।आधार स्टेशनों को ट्रैक करके, जिससे एक निश्चित समय पर एक फोन जुड़ा हुआ है, मालिक की स्थिति का अनुमान किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर लगाया जा सकता है।श्री सर्वेश कुमार, पीडब्लू 15, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, बीएसएनएल ने अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के निवास के लैंडलाइन फोन नंबर 05947-278170 का पंजीकरण प्रदान किया और प्रस्तुत किया कि 01.01.2012 की अवधि से पहले इस लैंडलाइन का कॉल विवरण हटा दिया गया है।उन्होंने कॉल विवरण की दो फोटोस्टेट प्रतियां स्वयं सत्यापित की।जांच अधिकारी ने यह भी कहा है कि यह लैंडलाइन फोन अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के आवासीय घर का है.आइडिया सेल्युलर कंपनी के नोडल अधिकारी श्री हुसैन एम. जादी, पीडब्लू 16, ने अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल, एक्सटेंशन 37 के मोबाइल फोन नंबर 983767689 और मोबाइल फोन नंबर 9837373774 के आईडी, एक्सटेंशन 38, श्री तुषार अग्रवाल, एसके अग्रवाल के पुत्र, अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के 31 भाई की आईडी को प्रमाणित और साबित किया है.इस गवाह ने कहा है कि इस गवाह के विभाग से एसओजी, उधम सिंह नगर को 26.11.2010 को कॉल विवरण प्राप्त हुए थे।इस गवाह ने अपने साक्ष्य के समय अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के मोबाइल फोन के 01.11.2010 से 26.11.2010 की अवधि के कॉल विवरण की स्वयं सत्यापित प्रतियां दाखिल की हैं.56. श्री राधे श्याम शुक्ला, पीडब्लू 17, एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी ने कहा है कि मोबाइल फोन नंबर 9760413695 अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा का है, जो 23.06.2008 को जारी किया गया था और मोबाइल फोन नंबर 9897136621 17.09.2009 को जारी किया गया था जो मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा निवासी बब्बू पुत्र

शमशुद्दीन का था।अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के अनुसार, इस मोबाइल फोन का उपयोग अपीलकर्ता जावेद द्वारा किया गया था.इस गवाह ने कहा है कि इन मोबाइल फोन नंबरों का कॉल विवरण एसओजी 57 को प्राप्त हुआ था।श्री अमित कुमार गंगवार, पीडब्ल्यू18 ने मृतक सचिन गुप्ता के मोबाइल फोन नंबर 8923049537 की आईडी साबित की।अपने साक्ष्य के समय, वह इस मोबाइल नंबर के मूल आईडी अभिलेख के साथ आया और अपनी स्वयं की सत्यापित प्रति, एक्सटेंशन 41 प्रस्तुत की।इस गवाह ने कहा है कि इस मोबाइल फोन का कॉल डिटेल एसओजी, उधम सिंह नगर को प्राप्त हुआ था।58. इंस्पेक्टर नरेश चंद्रा, पीडब्लू 14, तत्कालीन एसओजी, उधम सिंह नगर, ने इस तथ्य को साबित किया है कि ये सभी कॉल डिटेल उसे इन कंपनियों से प्राप्त हुए थे और जांच अधिकारी को सौंप दिए गए थे।32 59.जांच अधिकारी पी डब्ल्यू 13 श्री रविन्द्र कुमार ने कहा है कि जांच के दौरान उन्हें प्रभारी एस ओ जी 60 से कॉल डिटेल रिपोर्ट प्राप्त हुई।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१३ के से दिए गए बयानों में, अपीलार्थियों ने कहा कि घटना खंड पहले वे एक दूसरे खंड परिचित नहीं थे.अपीलार्थियों के ये बयान अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आलोक में झूठे पाए जाते हैं, और यदि अपीलार्थियों के बयान झूठे पाए जाते हैं, तो उन्हें एक लापता लिंक प्रदान करने और साबित परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ने के रूप में माना जा सकता है.इसलिए, उक्त उत्तरों पर अभियोजन पक्ष के सबूतों के संबंध में अपीलकर्ताओं के अपराध का निर्णय करने में विचार किया जा सकता है.61 श्री हुसैन एम. जादी, पीडब्लू 16, आइडिया सेल्युलर कंपनी के नोडल अधिकारी ने इस तथ्य को साबित किया कि मोबाइल फोन नंबर 9837667689 (अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल) और मोबाइल फोन नंबर 9760413695 (अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा) लगातार संपर्क में थे और इन मोबाइल फोनों पर दोनों तरफ से 24.11.2010 से 25.11.2010 तक और 24.11.2010 को 01.11.2010 से 03.00 बजे तक इन दोनों मोबाइल फोनों के बीच 8 बार बातचीत हुई थी।कॉल विवरण के आलोक में, गवाह राधे श्याम शुक्ला, पीडब्लू 17, नोडल अधिकारी, एयरटेल कंपनी ने साबित किया है कि मोबाइल फोन नंबर 9897136621, जिसका उपयोग अपीलकर्ता जावेद द्वारा किया गया था, और मोबाइल फोन नंबर 9760413695, अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा लगातार संपर्क में थे और इन मोबाइल फोनों पर 24.11.2010 को 23 बार और 25.11.2010 को लगभग 18 बार बातचीत हुई थी.62. यूनिनॉर कंपनी के नोडल अधिकारी श्री अमित कुमार गंगवार, पीडब्लू18, ने मृतक सचिन गुप्ता, एक्सटेंशन का. 41, और 33 की मोबाइल फोन संख्या 8923049537 की आईडी को साबित कर दिया और कहा कि कॉल विवरण के अनुसार, कागज संख्या 3Ka/11, मृतक सचिन गुप्ता का मोबाइल फोन नंबर और संदिग्ध मोबाइल फोन नंबर 9458222568 लगातार संपर्क में थे और इन मोबाइल फोनों के बीच 24.11.2010 को 13.05 बजे शाम से 14.49 बजे तक और 24.11.2010 को 06.03 बजे अपराह्न को सुचना देने वाले के मोबाइल फोन नंबर 9412091051 पर सुचना

देने वाले सचिन गुप्ता के मोबाइल फोन से बात की गई।उस समय इन मोबाइल फोनों की लोकेशन काशीपुर शहर में अलग-अलग जगहों पर थी।गवाह श्री हुसैन एम. जादी-पीडब्ल्यू-16, नोडल अधिकारी, आइडिया सेल्युलर कंपनी के अनुसार, अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के मोबाइल फोन का स्थान भी 24.11.2010 को शाम 06.07 बजे काशीपुर में था।63. श्री रविन्द्र कुमार, पी डब्लू 13, जांच अधिकारी ने कहा है कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक अज्ञात आईडी पर संदिग्ध मोबाइल नंबर 9458222568 को 05.10.2010 को सक्रिय किया गया था।जांच में, यह पाया गया कि अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के मोबाइल फोन पर इस संदिग्ध मोबाइल फोन नंबर से 05 अक्टूबर, 2010 को 11 बजे एसएमएस भेजा गयाः23:26 पूर्वाहन और उसके पश्चात अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल ने इस संदिग्ध मोबाइल फोन पर एसएमएस भेजा.यह भी पता चला कि ७. १०. २०१० को मोबाइल फोन नं. ९९२७७१५८७५ पर एक कॉल की गई, जिसका उपयोग अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल की पत्नी द्वारा किया गया और इस संदिग्ध मोबाइल फोन से अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के निवास के लैंडलाइन पर तीन बार कॉल किए गए.जांच के दौरान, यह भी पता चला कि अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल ने बीएसएनएल सिम नंबर-9458222568, संदिग्ध नंबर खरीदा और मृतक सचिन गुप्ता के मोबाइल फोन पर मृतक से बात किया करता था.34 64।इन गवाहों के साक्ष्य घटनाओं के विश्वसनीय, सच्चे और सही संस्करण पाए जाते हैं।इसलिए, इसके खंडन और खंडन की जिम्मेदारी अपीलार्थियों पर स्थानांतरित हो गई, जिसे वे निर्वहन करने में विफल रहे हैं.जब पूरी सामग्री को दंड प्रक्रिया संहिता की खंड ३१३ के से अपीलार्थियों के समक्ष रखा गया था, तो अपीलार्थियों ने केवल इसका खंडन किया था, लेकिन इस पहलू पर अपने बचाव में किसी साक्ष्य का नेतृत्व नहीं किया है.इसलिए, अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूतों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जो निर्णायक रूप से अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ता है.2017 की विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 2302 शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और बैच, 30.01.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः(1) चूंकि 12 अक्टूबर, 2017 के आदेश में उल्लिखित इस विशेष अनुमति अधिवक्ता में विचार के लिए समान प्रश्न उठाया विद्वान है, हमने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की स्वीकार्यता के प्रश्न पर श्री जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अनन्या घोष की सहायता से सुना है।हमने भारत सरकार की ओर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यशांक अधारु और विद्वान अधिवक्ता सुश्री शिरीन खजूरिया को भी सुना है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख (4) से शर्तों की प्रयोज्यता के प्रश्न पर इस आशय की आशंका व्यक्त की गई थी कि यदि कोई कथन साक्ष्य के रूप में दिया गया था तो संबंधित युक्ति के प्रचालन या सुसंगत क्रियाकलापों के प्रबंधन के संबंध में उत्तरदायी पद पर आसीन व्यक्ति खंड उक्त उपबंध के निबंधनों के अनुसार एक प्रमाणपत्र अपेक्षित था।यह प्रस्तुत किया गया कि यदि

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रासंगिक था और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो उस उपकरण की अभिरक्षा में नहीं था जिससे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज तैयार किया गया था, तो ऐसे प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं हो सकती थी।यह प्रस्तुत किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की खंड ६५ बी प्रासंगिक स्वीकार्य साक्ष्य को साबित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक प्रावधान था अग्रेतर इसका आशय यह घोषणा करके इस बिंदु पर कानून को पूरक बनाना था कि कथित प्रावधान के दायरे में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में किसी भी जानकारी को मूल के अतिरिक्त सबूत के बिना एक दस्तावेज माना जाएगा अग्रेतर किसी भी कार्यवाही में स्वीकार्य होगा.इस प्रावधान को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता पर मौजूदा कानून के अल्पीकरण के रूप में नहीं देखा जा सकता।हमें कुछ निर्णयों के माध्यम द्वारा लिया गया है जिनका उल्लेख किया जा सकता है।राम सिंह और अन्य बनाम कर्नल राम सिंह, 1985 (अनुपूरक) एस. सी. सी. 611 में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने उक्त मुद्दे पर विचार किया।आर. बनाम भारत संघ वाले मामले में अंग्रेजी निर्णयमकसूद अली, (1965) 2 आल ई० आर० 464, और आर ० वि० 1965। रॉबसन, (1972) 2 एएलईआर 699 और अमेरिकन लॉ, जैसा कि अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस 2 डी (वॉल्यूम. 29) पृष्ठ 494 में उल्लेख किया गया है, इस प्रभाव के अनुमोदन के साथ उद्धृत किए गए थे कि नई तकनीकों और नए उपकरणों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य लाभों के कानून से वंचित करना गलत होगा, बशर्ते रिकॉर्डिंग की सटीकता साबित की जा सके।ऐसे सबूतों पर हमेशा कुछ सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और प्रत्येक मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए।इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को उसकी प्रामाणिकता के बारे में न्यायालय द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों के अधीन स्वीकार्य माना गया था।5 टेप-अभिलेखिंग के मामले में यह देखा गया कि वक्ता की आवाज की विधिवत पहचान की जानी चाहिए, अभिलेख के निर्माता द्वारा बयान की सटीकता साबित करने की आवश्यकता थी, छेड़छाड़ की संभावना को खारिज करने की आवश्यकता थी।साक्ष्य के टुकड़े की विश्वसनीयता निश्चित रूप से एक तथ्य स्थिति के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।यद्यपि किसी इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य की आरंभिक ग्राह्यता को किसी तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता यदि वह प्रासंगिक हो।तुकाराम एस. दिघोले बनाम माणिकराव शिवाजी कोकाटे, (2010) 4 एस. सी. सी. 329 में इसी सिद्धान्त को दोहराया गया था।इस न्यायालय ने कहा कि नई तकनीकें और उपकरण आज के समय की बात है।यद्यपि ऐसे उपकरण छेड़छाड़ के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, फिर भी ऐसा कोई व्यापक नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसके द्वारा ऐसे साक्ष्य की स्वीकृति का निर्णय किया जा सके।इसकी प्रामाणिकता और सटीकता के प्रमाण का मानक अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों की तुलना में अधिक कठोर होना चाहिए।(5) टोमासो ब्रूनो और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2015) 7 एस. सी. सी. 178

की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह मत व्यक्त किया कि सूचना प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक मनोवृत्ति की उन्नति अन्वेषण की पद्धति में अवश्य होनी चाहिए।तथ्यों को स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रासंगिक थे।Scientific और electronic evidence एक जांच एजेंसी के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है।इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ मोहम्मद के मामले में दिया गया था।अजमल आमिर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012) 9 एससीसी 1 और राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम नवजोत संधू, (2005) 11 एससीसी 600।यद्यपि हम अनवर पी. बनाम वी. पी. के. बशीर और अन्य, (2014) 10 एस. सी. सी. 473, तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिया गया, में इस न्यायालय के निर्णय के प्रति भी निर्देश कर सकते हैं।पी. के. बशीर और अन्य, (2014) 10 एस. सी. सी. 473, तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिया गया।पैरा २४ में कथित निर्णय में यह पाया गया कि प्राथमिक साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की खंड ६२ द्वारा कवर किया गया था, जिसके लिए साक्ष्य अधिनियम की खंड ६५बी की प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं थी.यद्यपि द्वितीयक साक्ष्य के लिए, साक्ष्य अधिनियम की खंड 65 बी की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था और नवजोत संध (ऊपर) में एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के द्वितीयक साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की खंड 63 और 65 के अन्तर्गत कवर किया जा सकता है, यह सही नहीं था.यद्यपि टॉमासो ब्रुनो यद्यपि राम सिंह (पूर्वोक्त) में तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ के निर्णयों को ध्यान में अभिलेख हुए, यह सुरक्षित रूप खंड अभिनिर्धारित किया जा सकता मात्र कि इलैक्ट्रानिक साक्ष्य स्वीकार्य मात्र यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 क यद्यपि 65 ख के अन्तर्गत उपबंध स्पष्टीकरण के रूप में मात्रं यद्यपि प्रक्रियात्मक उपबंध मात्रं।यदि 7 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रामाणिक और प्रासंगिक है तो उखंड निश्चित रूप खंड न्यायालय के उसकी प्रामाणिकता और स्वीकार्यता के लिए प्रक्रिया के बारे में संतुष्ट होने के अध्यधीन स्वीकार किया जा सकता है जैखंड कि क्या ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति धारा 65 बी (ज) के से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में है।साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 क और 65 ख को इस विषय पर पूर्ण संहिता नहीं ठहराया जा सकता।अनवर पी. वी. (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय ने पैरा 24 में स्पष्ट किया कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख से प्राथमिक साक्ष्य साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की खंड 65 क और 65 ख के अंतर्गत नहीं आता है। मुख्य सबूत न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़ है और साक्ष्य कानून के अनुभाग 3 में परिभाषित अभिव्यक्ति 'दस्तावेज़' का मतलब है कोई भी मामला जो कि किसी पदार्थ पर पत्र , आंकड़ों या अंकों या इनमे से दो से ज्यादा तरीकों से परिभाषित या उल्लिखित है , इस्तेमाल करने के लिए आशयित है, या वह मामले कि रिकॉर्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । (9)। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शब्द को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की खंड 2 (टी) में निम्नानुसार परिभाषित

किया गया है:"(क)" "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" "से अभिप्रेत है डाटा, रिकार्ड या सृजित डाटा, संग्रहीत, प्राप्त या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी गई छवि या ध्वनि, या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर जनित माइक्रो फिशे."8 (10)। अभिव्यक्ति डेटा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की खंड 2 (o) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।"" "डेटा" "का अर्थ है सूचना, ज्ञान, तथ्यों, अवधारणाओं या अनुदेशों का अभ्यावेदन जो औपचारिक रूप से तैयार किए जा रहे हैं या तैयार किए गए हैं, और जिन्हें संसाधित करने का इरादा है, संसाधित किया जा रहा है या किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किया गया है, और किसी भी रूप में (कंप्यूटर प्रिंटआउट सहित मैग्नेटिक या ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, पंच कार्ड, पंच टेप) या कंप्यूटर की मेमोरी में आंतरिक रूप से संग्रहीत किया जा सकता है।""" "(11) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के साक्ष्य अधिनियम की खंड 65 बी (4) के से प्रक्रियात्मक आवश्यकता की प्रयोज्यता मात्र तभी लागू की जानी है जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक 37 साक्ष्य एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो इस तरह के प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने की स्थिति में है, न कि विपरीत पक्ष के नियंत्रण में।"ऐसे मामले में जहां इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य किसी ऐसे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसके पास कोई उपकरण नहीं है, वहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 और 65 की प्रयोज्यता को अपवर्जित अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में, उक्त धाराओं के से प्रक्रिया निश्चित रूप से लागू की जा सकती है।यदि ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह उस व्यक्ति को न्यायाधीश खंड वंचित करना होगा जिसके पास प्रामाणिक साक्ष्य/गवाह है, लेकिन साबित करने के तरीके के कारण इस तरह के दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के अन्तर्गत प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में में अदालत द्वारा विचार खंड बाहर रखा जाता है, जिखंड पेश करने वाला पक्ष संभवतः सुरक्षित नहीं कर सकता है।इस प्रकार, खंड 65 बी (एच) के से प्रमाणपत्र की आवश्यकता हमेशा अनिवार्य नहीं होती है।(12) तदनुसार, हम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता पर विषय पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं, विशेष रूप से एक पक्ष द्वारा जिसके पास उपकरण नहीं है जिससे दस्तावेज पेश किया जाता है।ऐखंड पक्षकार खंड साक्ष्य प्रक्रियात्मक की धारा 65 ख (4) से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।66. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शफी मोहम्मद (पूर्वोक्त) के मामले में पारित निर्णय अनवर पी. वी. (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में प्रति-विचित्र है।हम अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की इस प्रस्तुतीकरण से सहमत नहीं हैं.शफीक अहमद (सुप्रा) वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायाधीशालय ने अनवर पी. वी. वाले निर्णय सहित पूर्वोक्त निर्णयों पर ध्यान देने के पश्चात स्पष्ट किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब भी न्यायाधीश का हित मांग करता है, न्यायाधीशालय द्वारा उक्त प्रक्रिया में ढील दी जा सकती है।इसलिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनुपात

से बंधे हुए हैं।67. षड्यंत्र से भी आरोप है और इस प्रयोजन के लिए भा.दं.सं. सं. की खंड 120-ख के उपबंधों से अवलंब लिया जाता है, जो निम्नानुसार हैःआपराधिक षड्यंत्र का दंड(1) जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार है, जहां ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया हो।जो कोई पूर्वोक्त रूप में दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक नहीं होगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।"68 आपराधिक षड्यंत्र एक स्वतंत्र अपराध है।षड्यंत्र को एक सतत अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए।षड्यंत्रकारी के साथ खुद को जोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को सह-षड्यंत्रकारी के रूप में दोषी ठहराया जाएगा।आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के तत्व इस प्रकार हैंःदो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई करार या तो (क) कोई अवैध कार्य करना या कराना, (ख) कोई ऐसा कार्य जो अपने आप में अवैध नहीं है, लेकिन अवैध तरीकों से किया गया है।69 षड्यंत्र एक गुप्त गतिविधि है।राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) बनाम नितिन गुणवंत शाह (पूर्वोक्त) वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साधारणतया एक षड्यंत्र गोपनीय रूप से रचा जाता है।न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए कि उक्त अपराध किया गया है या नहीं, पारिस्थितिक साक्ष्य पर विचार कर सकता है।इस प्रकार आपराधिक षड्यंत्र के मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य का अतिरिक्त महत्व है।केहर सिंह और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1988) 3 एस. सी. सी. 609 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने षड्यंत्र साबित करने में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रासंगिकता पर बल दिया क्योंकि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना लगभग असंभव है।मेजर ई. जी. बारसे बनाम बम्बई राज्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1762 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि अपराध का सार विधि को तोड़ने का करार है।इस तरह के समझौते के पक्षकार आपराधिक षड्यंत्र के दोषी होंगे, हालांकि किए जाने के लिए सहमत अवैध कार्य नहीं किया गया है।यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सभी पक्ष एक ही अवैध कार्य करने के लिए सहमत हों। इसमें कई कार्य शामिल हो सकते हैं।भारतीय दंड संहिता की खंड 43 के तहत अगर कोई कार्य असोध है या कानून द्वारा निषिद्ध है तो वह अवैध होगा।के. आर. पुरुषोत्तमन बनाम केरल राज्य, (2005) 12 एस. सी. सी. 631 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि षड्यंत्र का गठन करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का अवैध कार्य या अवैध साधनों से कोई कार्य करने के लिए एकत्र होना पहली और प्राथमिक शर्त है और यह आवश्यक नहीं है कि सभी षड्यंत्रकारियों को षड्यंत्र के प्रत्येक और प्रत्येक ब्यौरे की जानकारी होनी चाहिए।न

ही यह जरूरी है कि हर षड्यंत्रकारी किसी न किसी षड्यंत्रकारी कार्य में सक्रिय रूप से भाग ले।षडयंत्रकारियों के बीच समझौते का अनुमान आवश्यक निहितार्थों से लगाया जा सकता है।अधिकांश मामलों में षड्यंत्र पारिस्थितिक साक्ष्यों से साबित होते हैं, क्योंकि षड्यंत्र कभी-कभार ही होता है।71. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह स्थापित कानून मात्र कि अंतिम बार देखी गई एकमात्र परिस्थिति परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा नहीं करेगी।अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने सहदेवन और एक अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (सुप्रा) और कंसा बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य (सुप्रा) वाले मामले में निर्णय पर भरोसा किया।72. चमन लाल और एक अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य, 2018 (1) सीसीएससी 268 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थियों द्वारा मृतक का साबित अपहरण एक आपराधिक अपराध है और इसके साथ 'अंतिम बार एक साथ देखे जाने' की किसी भी घटना की तुलना में बहुत अधिक भयावह दोष 40 है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर और अन्य, (2000) 8 एससीसी 382 वाले मामले के निर्णय को निर्दिष्ट किया और कहा कि उस मामले में कुछ इसी तरह की तथ्य की स्थिति में, जहां मृतक का अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उसके शरीर को क्षत-विक्षत पाया गया था, यह अभिनिर्धारित किया कि प्राचीन नियम कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए सबूत का भार अभियोजन पर है, को एक जीवाश्म सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए मानो वह बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क की कोई प्रक्रिया स्वीकार नहीं करता है।यह प्रतिपादित किया गया था कि उपधारणा का सिद्धांत उपर्युक्त नियम के लिए पराया नहीं है, न ही यह साक्ष्य की विधि में नियम के रूप में तथ्य की उपधारणा के तात्पर्य को कम करेगा। उपरोक्त निर्णय का उल्लेख करने पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा था कि मृतक का अपहरण आरोपियों द्वारा किया गया था, वे ही जानते थे कि उसके साथ क्या हुआ था जब तक कि वह उनके साथ था और यदि अपहरण पश्चात कुछ ही समय में उसकी हत्या कर दी गई थी, तो अनुमत तर्क प्रक्रिया अदालत को यह अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगी कि आरोपी ने उसकी हत्या की थी।यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह के निष्कर्ष को बाधित किया जा सकता है, यदि अभियुक्त न्यायालय को यह बताएगा कि मृतक के साथ कम से कम तब तक क्या हुआ था जब तक वह उनकी हिरासत में नहीं था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर यह मत व्यक्त किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का आशय युक्तियुक्त संदेह के बाद अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन को उसके भार खंड राहत प्रदान करना नहीं था, बल्कि यह उन मामलों पर लागू होती थी, जिनमें अभियोजन उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा था, जिनखंड कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता था, जब

तक कि अभियुक्त, ऐखंड तथ्यों के संबंध में अपने विशेष ज्ञान के आधार पर कोई स्पष्टीकरण देने में सफल न हो जाए, जिसखंड न्यायालय को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जा सके।41 इस निर्णय का अनुपात इस मामले की कुछ समान तथ्य स्थिति में पूरी तरह से लागू होता है।73 अभियोजन पक्ष के गवाह सफदर अली, पीडब्लू 9, मुरादाबाद जिले के मुंडपंडे पुलिस स्टेशन मुंडपंडे के निवास ने 26.11.2010 को अपने तहरीर, एक्सटेंशन का-9 के माध्यम द्वारा मुंडपंडे पुलिस स्टेशन को सड़क के किनारे एक खाई में पड़े एक अज्ञात शव के बारे में सूचित किया।शव का पंचनामा थाना मुंडापंडे के तत्कालीन प्रभारी पुलिस चौकी करनपुर एसआई ऋषि कपूर ने गवाहों की उपस्थिति में किया और घटनास्थल से साधारण मिट्टी और खून से सने मिट्टी का नमूना लिया। एक्सट. का. 7 की जांच रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के चेहरे, गर्दन, कलाई और दोनों हाथों की उंगलियों और घुटने के नीचे चोट के निशान पाए गए थे।कांस्टेबल चमन सिंह ने बताया कि अज्ञात शव की पहचान मृतक सचिन गुप्ता के शव के रूप में की गई है।इस सूचना पर प्रत्यक्षदर्शी विष्णु गोपाल उपाध्याय, पीडब्लू 19, ने काशीपुर पुलिस स्टेशन को एक पत्र भेजा और सूचित किया कि बरामद शव लापता सचिन गुप्ता का है, जिसका मामला 2010 की अपराध संख्या 577 के रूप में काशीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।सूचना मिलपश्चात के पश्चात निवेदक राकेश गुप्ता वहां गए और शव की पहचान की और पोस्टमॉर्टम के पश्चात उसे काशीपुर ले आए।डॉ. अशोक कुमार, पीडब्लू3 ने मुरादाबाद के जिला अस्पताल में 26 नवम्बर, 2010 को मृतक सचिन गुप्ता के शव का पोस्टमार्टम किया।उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्स. का. 6 को साबित कर दिया।पोस्टमॉर्टम के दौरान मृतक के मृत शरीर पर निम्नलिखित चोट के निशान पाए गएः– (i) गर्दन के चारों ओर 42 सेमी x 3 सेमी, ठोड़ी के नीचे 5 सेमी, श्रमसाध्य निशान से 9 सेमी ऊपर, बाएं कान के नीचे 5 सेमी और दाएं कान के नीचे 6 सेमी।लिगेचर मार्क के से ऊतक इकाइमोसिस और रक्त के थक्के मौजूद, थायरॉयड ट्रेकिया और थायरॉयड हड्डी का फ्रैक्चर।बाएं कंधे के शीर्ष पर 8 सेमी x 5 सेमी.क्लैविकल हड्डी के नीचे बाएं सीने पर 4 सेमी x 2 सेमी.बायीं कलाई और हाथ पर 10 सेमी x 18 सेमी. (v) दाहिनी कलाई और हाथ पर 11 सेमी x 19 सेमी.डॉ. अशोक कुमार, पीडब्लू 3 के साक्ष्य के अनुसार, मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था और मृत्यु का समय 25.11.2010 को शाम 07.00 बजे के पश्चात था। इस गवाह ने कहा है कि गला घोंटने के कारण दम घुटने का कारण रस्सी हो सकता है।अभियोजन पक्ष के मामले को गला घोंटने के लिए प्रयुक्त हत्या हथियार 'रस्सी' अग्रेतर मृतक के अन्य सामान जैसे उसका बटुआ अग्रेतर तवेरा कार, जिसमें मृतक को होटल ताज कॉर्बेट, रामनगर ले जाया गया था, की बरामदगी से अग्रेतर पुष्ट किया जाता है।76 अपीलकर्ता विमल शर्मा को 04.12.2010 को गिरफ्तार किया गया था।एस. आई. नरेश पाल सिंह पी डब्ल्यू-11 ने कहा है कि अपीलकर्ता विमल शर्मा ने 05.12.2010 को मुरादापश्चात जिले के करनपुर, पी. एस.

मुंडापंडे के क्षेत्र में वह स्थान दिखाया था, जहां गला घोंटने के पश्चात मृतक सचिन गुप्ता के मृत शरीर को फेंक दिया गया था और उस स्थान से गवाह सफदर अली निवासी मुंडापंडे, जिला मुरादापश्चात की लिखित सूचना पर, मृतक सचिन गुप्ता का मृत शरीर 26.11.2010 को बरामद किया गया था।मृतक के शव की बरामदगी का स्थल मानचित्र, एक्सटेंशन का-28, जांच अधिकारी, पीडब्लू-13, रविन्द्र कुमार द्वारा साबित किया जाता है।पी डब्लू ११ के एस. एस. आई. नरेश पाल सिंह ने अग्रेतर कहा कि उसने गवाह मकबूल हुसैन, पी डब्लू ५. ७७ के सामने अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा के प्रकटीकरण पर, ५. १२. २०१० को हत्या का हथियार 'रस्सी' बरामद किया, जिसका इस्तेमाल मृतक सचिन गुप्ता के गला घोंटने में किया गया था.रवींद्र कुमार, पीडब्लू 13, जांच अधिकारी ने इस रिकवरी साइट की साइट प्लान, एक्सटीके. 27 को तैयार किया और साबित किया।एस. आई. नरेश पाल सिंह, पी डब्लू-11 ने रस्सी, एक्स. के. ए. 19 की वसूली का ज्ञापन साबित किया और कहा कि इस वसूली के समय अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा ने बताया था कि इस रस्सी का उपयोग मृत सचिन गुप्ता का गला घोंटने में किया गया था।स्वतंत्र गवाह मकबूल हुसैन, पीडब्लू 5 ने भी बरामद कॉर्ड एक्सटेक्ट 15 को साबित किया।एस. आई. नरेश पाल सिंह, पी डब्लू ११ के साक्ष्य की पूरी तरह से मकबूल हुसैन, पी डब्लू ५ के साक्ष्य के साथ पुष्टि की गई है, जिसमें इस गवाह ने यह भी कहा कि इस वसूली अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा ने बताया कि उस समय इस रस्सी का उपयोग मृतक सचिन गुप्ता का गला घोंटने में किया गया था.78. 27 जनवरी, 2011 को लगभग 17.45 बजे, पुलिस द्वारा अपीलकर्ता जावेद की पहचान पर एक तवेरा कार, जिसकी पंजीकरण संख्या यूए 06 एच-1870, एक बटुआ, जो उक्त कार में पड़ा था और उक्त बटुआ पासपोर्ट से, मृतक सचिन गुप्ता का मतदाता कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक की जमा की गई राशि और मृतक के नाम पर सिटी फैशन के दो आगंतुक कार्ड बरामद किए गए।ये बरामदगी उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित मारुवाकेदा गंज और नंदनगर औद्योगिक क्षेत्र के बीच एक भूखंड से की गई थी।इस वसूली कार्यवाही के समय गवाह जमील अहमद, पीडब्लू 8 मौजूद था।44-79 रविंद्र कुमार, पीडब्ल्यू13 द्वारा तवेरा कार, बटुआ और अन्य वस्तुओं की रिकवरी मेमो, एक्सटेंशन केए-30 को साबित किया गया है।इस गवाह ने कहा है कि आरोपी जावेद और गवाहों के हस्ताक्षर रिकवरी मेमो और कपड़े पर लिए गए थे, जिसमें अन्य बरामद वस्तुओं को रखा गया था और सील कर दिया गया था।इस गवाह के साक्ष्य की पुष्टि एक स्वतंत्र गवाह जमील अहमद, पीडब्लू 8, के साक्ष्य से की गई है।मारूवाकेदा गंज के निवासी इस स्वतंत्र गवाह ने कहा कि वह 27 जनवरी, 2011 की शाम को काशीपुर से अपने घर जा रहा था। रास्ते में, उसने पुलिस कर्मियों को देखा, जिन्होंने इस गवाह का नाम और पता पूछा।गवाह जमील अहमद, पीडब्लू8, ने रिकवरी मेमो, एक्सटीकेए-30 और सील किए गए कपड़े पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए, जिसमें

घटनास्थल पर अन्य बरामद वस्तुओं को सील कर दिया गया था।उन्होंने कहा कि तवेरा मॉडल कार मौके पर थी, जिसे दारोगा ने बरामद किया और उस समय 4-5 अन्य पुलिसकर्मी और कई अन्य लोग वहां मौजूद थे।यद्यपि इस गवाह ने कहा कि उसने वसूली स्थल पर किसी भी आरोपी को नहीं देखा और उसका हस्ताक्षर एक खाली कागज पर प्राप्त किया गया था.अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस बयान पर जोर दिया और प्रस्तुत किया कि गवाह जमील अहमद के इस बयान के आलोक में, कहा कि वसूली अविश्वसनीय है.लेकिन, वसूली ज्ञापन, एक्सटेंशन के-30 के सावधानीपूर्वक अवलोकन के पश्चात अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरणीकरण स्वीकार्य नहीं है.वसूली ज्ञापन, एक्सटेंशन का-30 के अवलोकन से, इस वसूली ज्ञापन को तैयार करने और उस पर लिखने के तरीके से कहीं भी यह संकेत नहीं मिला कि इस गवाह के हस्ताक्षर खाली कागजों पर लिए गए थे.दूसरी ओर, गहन जांच के पश्चात वसूली स्थल पर गवाह जमील अहमद, पीडब्लू 8 की उपस्थिति और वसूली की कार्यवाही के बारे में उसके साक्ष्य विश्वसनीय और किसी संदेह से मुक्त पाए गए हैं.इस गवाह के साक्ष्य से, रवींद्र कुमार, पीडब्लू 13 के साक्ष्य की पूरी तरह से पुष्टि की गई है कि अपीलकर्ता जावेद की पहचान पर बटुए और मृतक सचिन गुप्ता के अन्य सामान के साथ पंजीकरण संख्या यूए 06 एच-1870 वाली तवेरा कार बरामद की गई थी.अपीलकर्ता जावेद ने रिकवरी मेमो, एक्सटेंशन का-30 पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया था।यह भी ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि गवाह पीडब्लू 6, होटल ताज कॉर्बेट के मालिक, रईस अहमद ने अपने होटल के आगंतुक रजिस्टर को साबित किया और कहा कि 24.11.2010 को, विमल कुमार शर्मा ने इस रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि अपने स्वयं के हस्तलेख में दर्ज की थी और अपना कार नंबर यूए 06 एच-1870 और उसका मोबाइल नंबर 9760413695 दर्ज किया था, जो अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा से पुलिस द्वारा 04.12.2010 को बरामद किया गया था।गवाहों के साक्ष्य के समय रईस अहमद, पीडब्लू 6, बरामद तवेरा कार, एक्सटेंशन 20 को अदालत के समक्ष पेश किया गया था।तवेरा कार देखने पश्चात गवाह रईस अहमद, पी डब्लू 6 ने प्रमाणित किया कि इस तवेरा कार का पंजीकरण नंबर विमल कुमार शर्मा द्वारा अपने होटल के विजिटर रजिस्टर में दिनांक 24.11.2010 को दर्ज किया गया था।अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पुलिस के समक्ष अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा की स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य है।यह सच है कि पुलिस की हिरासत में रहते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी स्वीकारोक्ति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी, लेकिन, यहां तक कि जब कोई आरोपी पुलिस की हिरासत में होता है तो भी ऐसा कोई बयान देता है जो कथित अपराध से संबंधित सामग्री की बरामदगी या किसी भी तथ्य की खोज के लिए कुछ जानकारी प्रकट करता है, तो उसके विरुद्ध ऐसा बयान साबित किया जा सकता है।धारा 27 को तब प्रचालन में लाया जाता है जब पुलिस अभिरक्षा में कोई व्यक्ति

किसी ऐखंड स्थान खंड कोई वस्तु प्रस्तुत करता है जिससे संबंध उस अपराध खंड बताया जाता है जिससे मुखबिर अभियुक्त है और यह विधि में स्वीकार्य 46 है।दिल्ली प्रशासन बनाम बाल कृष्ण और अन्य, (1972) 4 एस. सी. सी. 659 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बरामद वस्तुओं की अवधारणा, उपयोग और साक्ष्य मूल्य का विश्लेषण किया और अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दी गई इतनी अधिक जानकारी के सबूत की अनुमति देती है, जो किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होने के दौरान दी जाती है, जो स्पष्ट रूप खंड इस तथ्य खंड संबंधित है कि इस तरह खंड खोजी गई जानकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के अन्तर्गत एक पुलिस अधिकारी के सामने की गई कोई भी स्वीकारोक्ति, चाहे वह अभिरक्षा में हो या नहीं, अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है।लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 इन धाराओं के लिए एक परन्तुक के रूप में है और एक बयान, यहां तक कि संस्वीकृति के माध्यम खंड भी, जो स्पष्ट रूप खंड खोजे गए तथ्य खंड संबंधित है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में वर्णित परिस्थितियों में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।अन्तर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (2004) 10 एस. सी. सी. 657 वाले मामले में पहले के विनिश्चयों का विश्लेषण करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की खंड 27 की विभिन्न अपेक्षाओं का सारांश इस प्रकार दियाः(1) वह तथ्य, जिसके बारे में साक्ष्य दिया जाना चाहा गया है, विवाद्यक के लिए सुसंगत होना चाहिए।यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस प्रावधान का प्रासंगिकता के प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है।खोजे गए तथ्य की प्रासंगिकता को इसे अपराध से जोड़ने वाले अन्य साक्ष्य की प्रासंगिकता से संबंधित आदेश अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए ताकि तथ्य का पता लगाया जा सके।(2) इस तथ्य का पता चला होगा।यह खोज अभियुक्त से प्राप्त किसी सूचना के परिणामस्वरूप की गई होगी न कि अभियुक्त के अपने कार्य के द्वारा।सूचना देने वाले व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए।वह किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होना चाहिए।47 (6) अभिरक्षा में किसी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज को अभिसाक्ष्य दिया जाना चाहिए।मात्र जानकारी का वह हिस्सा जो स्पष्ट रूप से या कड़ाई से खोजे गए तथ्य से संबंधित है, साबित किया जा सकता है।बाकी अस्वीकार्य है।82 मधु बनाम केरल राज्य, (2012) 2 एससीसी 399 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की खंड 27 के पीछे तर्क यह है कि प्रश्नगत तथ्य अभियुक्त द्वारा उसके प्रकटन के बिना अज्ञात रहते।इसलिए, तथ्यों की खोज स्वयं इकबालिया बयान की सच्चाई की पुष्टि करती है और चूंकि यह सच है कि किसी न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की खंड २७ की खोज करने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की खंड २५ और २६ में निहित जनादेश के अपवाद के रूप में शामिल किया गया है.तत्काल मामले में, की गई वसूलियां, जब अपीलार्थी, विमल

कुमार शर्मा और जावेद हिरासत में थे, स्थापित हो गई हैं.वसूली प्रकटीकरण के बयानों पर आधारित है।इन बरामदगियों के संबंध में अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूतों की एक अध्ययन जांच पर, हमें कुछ भी नहीं मिला है कि ये बरामदगियां वास्तव में इन अपीलार्थियों की जानकारी पर नहीं की गई हैं और पुलिस द्वारा लगाई गई हैं.84. अपीलार्थियों के विद्वत वकीलों ने प्रस्तुत विद्वान कि प्राथमिकी में फिरौती की कोई राशि नहीं है, अपीलकर्ताओं विमल कुमार शर्मा और जावेद के नाम, सूचना देने वाले के दूसरे तहरीर में गवाह-दीप अरोड़ा-पीडब्ल्यू-4 और खैरती लाल के नाम शामिल हैं और इसलिए, अभियोजन का मामला स्वीकार्य नहीं है।48-85। निवेदक राकेश गुप्ता-पीडब्लू-1 ने कहा है कि २५. ११. २०१० को दीपक अरोड़ा और खैरती लाल ने अपराध करने में सभी तीन अपीलार्थियों की संलिप्तता का खुलासा किया.यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि प्राथमिकी एक विश्वकोश नहीं है जिसमें घटना के सभी विवरण होने चाहिए।प्राथमिकी में अभियोजन पक्ष के मामले के सभी विवरण शामिल होने की उम्मीद नहीं है।यह पर्याप्त हो सकता है, यदि घटना के बारे में अभियोजन पक्ष के मामले के व्यापक तथ्य प्रकट हों।अपीलार्थियों या गवाहों के नामों के बारे में चूक अभियोजन के लिए घातक नहीं हो सकती है।चूंकि प्राथमिकी बिना अनावश्यक विलम्ब के दर्ज की जाती है, इसलिए जब तक कि मनगढ़ंत के संकेत न हों, न्यायालय मात्र चूक के कारण प्राथमिकी में दिए गए अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार नहीं कर सकता है।रतन सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (1997) 4 एस. सी. सी. 161 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि दांडिक न्यायालयों को प्रथम सूचना कथन में मात्र लोप के साथ तुच्छ नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे कथन से न तो यह आशा की जा सकती है कि जो हुआ उसके प्रत्येक ब्यौरे का वृत्तांत होगा और न ही यह आशा की जा सकती है कि उसमें घटनाओं की एक विस्तृत सूची होगी।जो व्यक्ति अधिकारियों को पहली जानकारी देता है वह तथ्यों के साथ ताजा हो सकता है, लेकिन उसके पास आवश्यक रूप से बिना किसी कमी के पूरी कहानी के विवरणों को पुनः प्रस्तुत करने का कौशल या योग्यता नहीं होनी चाहिए।कुछ लोग एक वर्णन में महत्वपूर्ण विवरणों को भी याद कर सकते हैं।86 यू. पी. राज्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 488.नरेश और अन्य, (2011) 4 एस. सी. सी. 324, सिद्धान्त को दोहराते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि यह सुस्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि प्राथमिकी पूरे मामले का विश्वकोश नहीं है।इसमें सभी विवरण शामिल नहीं हो सकते हैं और इसकी आवश्यकता भी नहीं है।वर्तमान मामले में बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के एफ. आई. आर. प्राथमिकी की गई थी और जो स्वयं अभियोजन पक्ष के मामले को आश्वासन देती है।प्राथमिकी का उद्देश्य कानून को गति देना है।फिरौती की रकम का उल्लेख न करना, प्राथमिकी में अपीलकर्ताओं और गवाहों के 49 नाम, अभियोजन पक्ष के मामले के लिए शायद ही घातक हो सकते हैं।87. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों

को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष के विश्वसनीय, भरोसेमंद और ठोस साक्ष्य और कानून की पूर्वोक्त स्थिर स्थिति को देखते हुए, हम अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को प्रतिग्रहण करना करने के लिए तैयार नहीं हैं कि प्राथमिकी में फिरौती की राशि, अपीलकर्ताओं विमल कुमार शर्मा और जावेद और गवाहों के नाम का लोप अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है।88. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मुखबिर ने मात्र संदेह पर प्राथमिकी दर्ज की यद्यपि तर्क दिया कि संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है।अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने मोहम्मद फैजान अहमद उपनाम कालू बनाम बिहार राज्य (सुप्रा) और राकेश बनाम राज्य (सुप्रा) में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया। यद्यपि हमें अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई इस तरह की प्रस्तुतियों के समर्थन में अभिलेख पर कोई सबूत या सामग्री नहीं मिलती है.दूसरी ओर, अपराध में अपीलार्थियों की भागीदारी अभियोजन द्वारा पेश किए गए विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य के प्रकाश में साबित होती है.अपीलार्थियों के विरुद्ध यह मामला केवल संदेह पर आधारित नहीं है.अपीलार्थियों के विरुद्ध मामला ठोस सबूतों के मजबूत आधार पर आधारित है।परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई है ताकि अपीलकर्ताओं के अपराध को घर लाया जा सके.89. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अन्तर्गत उनकी जांच करते समय अपीलार्थियों को पारिस्थितिक साक्ष्य के प्रासंगिक दोषारोपण में खंड कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया था, इसलिए, दोषसिद्धि को अपास्त किया जा सकता है।अपीलार्थियों के विद्वत 50 वकीलों ने नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (सुप्रा) और भारत बनाम राज्य (सुप्रा) के निर्णयों पर भरोसा किया । दूसरी ओर, राज्य और मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१३ के अन्तर्गत अपीलार्थियों खंड सभी प्रासंगिक प्रश्न पूछे गए थे.दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के उपबंधों के अनुपालन में प्रत्येक त्रुटि या चूक आवश्यक रूप खंड विचारण को दूषित नहीं करती है।अपीलार्थियों के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं होगा कि उनसे किसी विशेष परिस्थिति पर सवाल नहीं किया गया था.उन्हें यह दिखाना चाहिए कि इस तरह की जांच न किए जाने से वास्तव में और भौतिक रूप से उन्हें प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप न्यायाधीश की विफलता हुई है।न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लि

ए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि अपीलार्थियों पर किस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, डाला गया था, जबकि अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जानकारी थी।दूसरी ओर, उनके उत्तर झूठे पाए जाते हैं जैसे कि घटना से पहले वे एक-दूसरे को नहीं जानते थे।अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सफल रहा है कि मृतक का अपीलार्थियों द्वारा फिरौती के लिए साजिश के साथ अपहरण किया गया था और उसके बाद मृतक

की हत्या कर दी गई थी, इसलिए, अनुमत तर्क प्रक्रिया न्यायालय को यह अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगी कि अपीलार्थियों ने उसकी हत्या की थी.91. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह इंगित किया गया है कि जांच में बड़ी खामियां हैं क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा, दूसरों के अलावा, संदिग्ध मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, मृतक का मोबाइल फोन बरामद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, बरामद की गई रस्सी को एफएसएल को भेजने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, स्थान की योजना तैयार नहीं की गई थी जहां गवाह दीपक अरोड़ा, पीडब्ल्यू4 ने 24.11.2010 को अपीलकर्ता विमल शर्मा और अपीलकर्ता जावेद के साथ 51 मृत लोगों को देखा था.अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषपूर्ण जांच के कारण, दोषसिद्धि को अपास्त किया जा सकता है.अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वसीफ हैदर और अन्य (पूर्वोक्त) मामले में निर्णय पर भरोसा किया।92. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्ताओं की दोषमुक्ति के तर्क का मूल्यांकन करने के लिए , यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रत्येक दोषपूर्ण जांच का परिणाम अनिवार्य रूप से बरी होना नहीं है।यह केवल दोषपूर्ण जांच के परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं को बरी करना नहीं होगा.93 कर्नल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1995) 5 एस. सी. सी. 518 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दोषपूर्ण अन्वेषण के मामलों में न्यायालय को साक्ष्य के मूल्यांकन में सतर्कता बरतनी होगी किंतु किसी अभियुक्त व्यक्ति को केवल दोष के कारण दोषमुक्त करना उचित नहीं होगा।94 यह अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही अन्वेषण अनुचित या दोषपूर्ण हो, शेष साक्ष्य की उसके प्रभाव से स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए।वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह के बाद अपीलकर्ताओं के अपराध को स्थापित करने में सफल रहा है.अपीलार्थियों ने हमारे समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी है कि दोषपूर्ण जांच के कारण उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ था.कथित दोषपूर्ण जांच या जांच में कमी अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ तक नहीं जाती है।95. अपीलार्थियों के विरुद्ध अभिलेख पर साबित परिस्थितियों की श्रृंखला निम्नानुसार हैः52 (i) यह स्थापित है कि मृतक सचिन गुप्ता और अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल अच्छे दोस्त थे.जांच के दौरान यह पाया गया कि अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल ने बीएसएनएल सिम नंबर-9458222568, संदिग्ध नंबर खरीदा, जिससे वह अपने मोबाइल फोन पर मृतक से बात करता था.यह भी स्थापित किया गया है कि संदिग्ध मोबाइल फोन 05.10.2010 को सक्रिय किया गया था और 24.11.2010 तक उपयोग किया जा रहा था।यह भी स्थापित किया गया है कि मृतक और संदिग्ध मोबाइल फोन का मोबाइल फोन लगातार संपर्क में था और इन मोबाइल फोनों के बीच 13 से लगभग छह बार बात हुईःशाम 5.05 बजे से 14 बजे तक:24.11.2010 को अपराह्न 2.49 बजे, मृतक के अपहरण की तिथि।यह भी स्थापित किया गया है कि

अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल का मोबाइल फोन और अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा का मोबाइल फोन लगातार संपर्क में था और इन मोबाइल फोनों पर 24.11.2010 से 25.11.2010 तक 22 बार बात की गई थी।ये दोनों मोबाइल फोन लगातार संपर्क में थेः 1.00 बजे अपराह्न से 3:दिनांक 24.11.2010 को सायं 5.00 बजे और 8 कॉल की गई।यह भी स्थापित किया गया है कि मोबाइल फोन, जिसका उपयोग अपीलकर्ता जावेद और अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा के मोबाइल फोन द्वारा किया गया था, लगातार संपर्क में था और इन मोबाइल फोन पर 24.11.2010 को लगभग 23 बार और 25.11.2010 को लगभग 18 बार बात की गई थी।यह भी स्थापित किया गया है कि मृतक सचिन गुप्ता को अंतिम बार अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा और अपीलकर्ता जावेद के साथ सरकारी अस्पताल, काशीपुर के पास देखा गया था और वहां से ये तीनों व्यक्ति तवेरा कार में होटल ताज कॉर्बेट, रामनगर गए थे.53 (viii) यह भी स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल और अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा को लगभग 6 बजे मानपुर तिराहा, काशीपुर के पास एक साथ देखा गयाःउस समय अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था।यह भी स्थापित किया गया है कि अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल के मोबाइल फोन का स्थान मानपुर तिराहा, काशीपुर के पास पाया गया था.(x) यह भी स्थापित है कि मुखबिर को लगभग 6 बजे अपने बेटे सचिन गुप्ता के मोबाइल फोन से अपने मोबाइल फोन पर एक कॉल प्राप्त हुईःउस समय अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा की उपस्थिति भी उस स्थान पर पाई गई थी।यह भी स्थापित है कि अपीलकर्ता अखिल कुमार अग्रवाल ने 24.11.2010 की रात में सरकारी अस्पताल, काशीपुर के साइकिल स्टैंड पर मृतक की मोटरसाइकिल को मुखबिर को दिखाया.अभियोजन पक्ष के गवाह डॉ. अशोक कुमार के अनुसार, मृतक सचिन गुप्ता की मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था जो रस्सी के कारण हो सकता है।यह भी स्थापित किया गया है कि कथित रस्सी अपीलकर्ता विमल कुमार शर्मा की पहचान पर बरामद की गई थी.यह भी स्थापित किया गया है कि कथित तवेरा कार और मृतक सचिन गुप्ता के अन्य सामान के साथ बटुआ अपीलकर्ता जावेद की पहचान पर बरामद किया गया था.(xv) यह भी स्थापित किया गया है कि अपीलार्थियों द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की खंड 313 के से झूठे बयान दिए गए थे, जो परिस्थितियों की श्रृंखला में उनके विरुद्ध अभिलेख पर एक अतिरिक्त लिंक 54 है।96. अपीलार्थियों के विरुद्ध परिस्थितियों की पूर्वोक्त श्रृंखला निर्णायक प्रकृति की है।यह एक पूरी श्रृंखला है जो दिखाती है कि सभी मानव संभावनाओं में, अपराध अपीलार्थियों द्वारा किया गया है.इसलिए, अभिलेख में रखे गए सभी सबूतों की फिर से समीक्षा करने के बाद, हम निचली विचारण न्यायालय से सहमत हैं।यह एक उचित मामला नहीं है जहां आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।97.

कारणों से, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ये तीनों अपील खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, और तदनुसार इन्हें खारिज किया जाता है।

(आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति) **(सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति)**

02.09.2019

जेकेजे